

विनियामक फॉरबीयरेंस: एक आपातकालीन औषधि, न कि मुख्य आहार।

“जो लोग अतीत से सबक नहीं लेते, वो इसे दोहराने का अपराध करते हैं”
-जॉर्ज संतायाना, स्पेनिश दार्शनिक

बैंक ऋणों पर वर्तमान विनियामक फॉरबीयरेंस कोविड महामारी के कारण जरूरी हो गया है। यह अध्याय वर्तमान समय के लिए महत्वपूर्ण सबक निकालने के लिए 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जी.एफ.सी.) के बाद अपनाई गई विनियामक फॉरबीयरेंस की नीति का अध्ययन करता है। बैंकों के लिए विनियामक फॉरबीयरेंस जिसमें पुनर्गठित परिसम्पत्तियों के लिए मानदण्डों को शिथिल करना शामिल था, जहां पुनर्गठित परिसंपत्तियों को अब गैर-निष्पादित अस्तित्यों (इसके पश्चात एन पी ए) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी तथा इसलिए एनपीए को आकर्षित करने वाले स्तरीय प्रावधानों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। संकट के दौरान, कर्जदारों को संकट से होने वाले अस्थाई कठिनाईयों से पार जाने में फॉरबीयरेंस ने सहायता की तथा एक बड़े संसर्ग के प्रवाह में आने से बचाया। हालांकि, फॉरबीयरेंस को सात वर्षों तक जारी रखा गया, जबकि इन्हें 2011 में बंद हो जाना चाहिए था, जब ऋण विकास, जीडीपी, निर्यात आई आई पी सभी इससे उभर चुके थे। फिर भी फॉरबीयरेंस आर्थिक वसूली के बाद लम्बे समय तक जारी रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि बैंकों, फर्मों और अर्थव्यवस्था के लिये यह अनपेक्षित और हानिकारक साबित हुआ। आवश्यक रियायती प्रावधान को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने ऋण लेने की बाध्यता को अनुचित संस्थाओं के लिये भी पुनर्गठित करने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया जिससे रियायतों ने उनकी गलतियों को भुनाने का काम किया। कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया लाभ तब शेरधारकों को बढ़े हुए लाभांश का भुगतान करने में बैंकों द्वारा उपयोग किया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के मामले में इसमें सरकार भी शामिल थी। इसका नतीजा यह हुआ कि बैंक आर्थिक रूप से बुरी तरह कमजोर हो गए। इस प्रकार कम पूंजी बैंकों को बंद होने के कगार पर ले आई। प्रोत्साहन को विकृत कर दिया और जोखिमपूर्ण उधार देने की प्रथाओं को बढ़ावा दिया, इसमें ऐसी संस्थाओं/लोगों को उधार देना भी शामिल था जो अस्तित्व में भी नहीं थे। विकृत प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप, बैंकों ने ऋण को गलत तरीके से भुनाया, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा। बैंकों की इस उदारता से लाभान्वित फर्मों ने भी असम्भव परियोजनाओं में निवेश किया। आकस्मिक आपूर्ति और शिथिल निगरानी की इस पद्धति में ऋण प्राप्त करने के लिए उधार लेने वाली फर्म के प्रबन्धन की क्षमता ने फर्म के भीतर अपने प्रभाव को मजबूत किया, जिससे फर्मों की शासन प्रक्रिया में स्थिरता आई। फर्मों के बोर्डों की गुणवत्ता गिर गई। इसके बाद, संसाधनों की हेराफेरी बढ़ गई और फर्मों का निष्पादन बिगड़ गया। जब 2015 में फॉरबीयरेंस समाप्त हो गई, तब तक पुनर्संरचना सात गुणा तक बढ़ चुकी थी और अनर्जक अस्तियां पूर्व फॉरबीयरेंस की तुलना में लगभग दो गुणा हो चुकी थी। इस बात की चिंता करते हुए कि बैंकों की वास्तविक स्थिति उनकी बहियों में परिलक्षित स्थिति से भी बदतर हो सकती है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बहियों को सही करने के लिए एसैट क्वालिटी रिव्यू (AQR) को आरंभ किया। 2014-15 में जब सकल एनपीएस 4.3 से बढ़कर 2015-16 में

7.5 प्रतिशत हो गया था और 2017-18 में 11.2% पर था तब, एक्यूआर बैंकों की बहियों में प्रच्छन्न खराब आस्तियों को सामने लाने में विफल रहा और पूंजीगत आवश्यकताओं का आकलन कमतर हुआ। एक्यूआर डिजाईन के साथ जुड़ाव के माध्यम से बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक नहीं समझे गए, जिससे बैंकों का पूंजीकरण तेजी से बढ़ा। इसने ऋण देने की विकृतियों के एक दूसरे दौर को जन्म दिया, जिससे पहले से भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई।

जीएफसी के बाद लंबे समय से चली आ रही फॉरबीयर्स नीतियों के कारण हाल ही में बैंकिंग संकट बढ़ा है और इससे निवेश की दरों में कमी आई है और देश में आर्थिक विकास में भी कमी आई है। नीति निर्माताओं के लिए पहला सबक आपातकालीन उपायों का सही तरीके से उपचार करना है और ठीक होने के बाद भी उनका विस्तार नहीं करना है: जब कोई आपातकालीन औषधि एक मुख्य आहार बन जाती है, तो इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है। दूसरा, जबकि पिछली घटना से मिली सीख को पुनरावृत्ति से बचने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए, इस सर्वेक्षण के अध्याय-7 में उजागर अंतर्दृष्टि द्वारा जटिल घटनाओं के एक्स पोस्ट विश्लेषण को अनुशासित किया जाना चाहिए विशेषकर, नीति निर्धारण को सक्षम बनाने हेतु, जिसमें अनिश्चितता के बीच निर्णय लेने का अभ्यास शामिल होता है, एक्स पोस्ट जांच द्वारा पूर्वाग्रह की भूमिका को पहचाना जाना चाहिए और गलत या खराब या इरादतन लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप प्रतिकूल निष्कर्षों के समान गलती नहीं करनी चाहिए।

परिचय

7.1 कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए, दुनिया भर के वित्तीय नियामकों ने विनियामक फॉरबीयर्स को अपनाया है। भारत कोई अपवाद नहीं है। वास्तविक क्षेत्र की वित्तीय क्षेत्र में विफलताओं को रोकने के लिए आपातकालीन उपायों जैसी रियायतें (फॉरबीयर्स) जिससे संकट को अधिक गहरा होने से बचाया जा सकता है। इसलिए आपातकालीन चिकित्सा के रूप में, नीति निर्माताओं के औजारों में रियायतें (फॉरबीयर्स) एक वैध स्थान रखती हैं; रियायतों हेतु आर्थिक तर्क की व्याख्या के लिए देखें बॉक्स-1। हालांकि, इसमें सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि आपातकालीन औषधि एक मुख्य आहार न बन जाए, क्योंकि उधारकर्ता और बैंक आसानी से ऐसे पैलीवेटिव के आदी हो जाते हैं। जब आपातकालीन औषधि एक मुख्य आहार बन जाती है तो नकारात्मक दुष्प्रभाव न केवल बढ़े हो सकते हैं बल्कि एक लम्बी अवधि तक भी रह सकते हैं। इसलिए भावी नीति के मार्गदर्शन के लिए पिछली रियायत धाराओं के क्रियान्वयन के निहितार्थों की सावधानी पूर्वक जांच करना और समझना प्रासंगिक है। 2008 में, वैश्विक वित्तीय संकट का अनुमान लगाते हुए आर बी आई ने विनियामक रियायतों (फॉरबीयर्स) की नीति प्रस्तुत की। इसने दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्गठन के मानदण्डों को शिथिल किया-आस्तियों को गैर-निष्पादित स्थिति में डाउन ग्रेड करना अब अनिवार्य नहीं था और इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी; इसके विवरण और समय अवधि के लिए बॉक्स-2 देखें। यह अध्याय मौजूदा समय के लिए महत्वपूर्ण सबकों को एकत्र करने हेतु सामान्य रूप से बैंकों, फर्मों और अर्थव्यवस्था पर 2008 की रियायतों के प्रभाव का अध्ययन करता है। जैसा कि स्पेनिश दार्शनिक जार्ज संतायना ने चेताया है कि “जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं, वे इसे दोहराने का अपराध करते हैं।”

बॉक्स-1 फॉरबीयर्स (रियायतों) हेतु आर्थिक औचित्य

दबावग्रस्त आस्तियों से रियायत के साथ और रियायत के बिना निपटने के दौरान निम्नलिखित उदाहरण बैंकों की पसंद का वर्णन करता है। इस संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब कोई बैंक ऋण के नुकसान के कारण अतिरिक्त प्रावधान करता है, तो बैंक के मुनाफे में गिरावट आती है और इस कारण बैंक की इक्विटी पूंजी में कमी आती है। इसलिए खराब ऋणों के लिए प्रावधान के प्रोत्साहन का विनियामक (फॉरबीयर्स) रियायतों पर अत्यधिक प्रभाव होता है।

रियायतों के बिना	रियायतों के साथ
1. यदि परियोजना व्यवहार्य है, तो बैंक आस्तियों का पुनर्वर्णन करेगा और इसे गैर निष्पादित परिसम्पत्ति (एनपीए) में बदल देगा। और इसके लिए प्रावधान करेगा।	2. यदि परियोजना व्यवहार्य है, तो बैंक ऋण का पुनर्गठन नहीं करेगा और आस्तियों को गैर-निष्पादित घोषित करेगा। महत्वपूर्ण रूप से, इस मामले में अव्यवहार्य परियोजना के पुनर्गठन द्वारा बैंकों को कुछ नहीं मिलेगा।
2. यदि परियोजना व्यवहार्य है, तो बैंक आस्तियों का पुनर्वर्णन करेगा और पुनर्गठित आस्तियों से (एनपीए) के रूप में समान स्तर के प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती है, गैर जरूरी प्रावधान किये जाते हैं।	2. पूंजी की कमी वाले बैंक प्रावधानों को कम करने और पूंजी पर परिणामी हित से बचने के लिए अव्यवहार्य परियोजनाओं के पुनर्गठन के लिए एक प्रोत्साहन है।

अनुपस्थिति रियायत, एक बैंक को फर्म/परियोजना को व्यवहार्यता के आधार पर पुनर्गठन का निर्णय लेना चाहिए क्योंकि एक अव्यवहार्य फर्म के पुनर्गठन की लागत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन, जवाबदेही के साथ, बैंकों को पुनर्गठन से किसी निकटवर्ती लागत का नुकसान नहीं होता है। इसलिए बैंक पुनर्गठन करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह विकल्प उन्हें कम एनपीए घोषित करने और ऋण प्रावधान के कारण लागत से बचने की अनुमति देता है। इस प्रकार रियायतें बैंकों को दबावग्रस्त आस्तियों के पुनर्गठन पर जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है, फिर भले ही वह अव्यवहार्य क्यों न हों। पूंजी की कमी वाली संस्थाएं विशेष रूप से जोखिम भरी परियोजनाओं में निवेश करने के प्रति अति संवेदनशील होती है, यह एक परिकल्पना है जिसे गैर-लाभदायक साहित्य में जोखिम-अंतरण कहा जाता है (जेन्सेन एवं मेकलिंग, 1976)। उन मामलों पर विचार करें जहां एक उधारकर्ता के ऊपर बैंक का बड़ा बकाया है, जो डिफाल्ट के कगार पर है। यदि उधारकर्ता चूक करता है तो, बैंक को ऋण की पहचान एनपीए के रूप में करनी होगी, नुकसान उठाना होगा, और संभवतः खराब पूंजी की वजह से उसका पुनः पूंजीकरण करना होगा। उधारकर्ता की शोधन-क्षमता को देखते हुए, नए ऋण को देना, या उसके वर्तमान ऋण का पुनर्गठन करना अत्याधिक जोखिम भरा है और इसके परिणाम स्वरूप बैंकों का अधिक नुकसान हो सकता है। हालांकि इस अप्रत्याशित स्थिति में नए ऋण उधारकर्ता को पुनःप्राप्त करने में मदद करता है, तो बैंकों को अपने सभी ऋण ब्याज सहित वापिस मिल जाएंगे और इसलिए पूंजी में कोई कमी नहीं होगी। परन्तु इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नुकसान की मान्यता इक्विटी धारकों को प्रभावित करती है। उन्हें अपने निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं मिलता है और पर्याप्त पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए पुनःपूंजीकरण के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे परिदृश्य में, पूंजी की कमी वाला बैंक, जहां इक्विटी मालिकों के पास कम “स्किन इन द गेम” है, जोखिम भरे उधारकर्ता को उधार देने की संभावना होती है। कम पूंजी के साथ, इक्विटी मालिकों के पास संभावित परिदृश्य में नए उधार से कम खोने के लिए होता है, जहां उधारकर्ता विफल रहते हैं हालांकि फर्म के पुनःसुधार की संभावना नहीं होने का परिणाम उनके लिए एक महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होगा। जोखिम निवेश के मामले में अजमाकर्ताओं के पास कोई मार्जिनल अप-साइड नहीं होता है लेकिन अगर फर्म विफल हो जाती है तो कुछ कीमत उठानी पड़ सकती है। इसलिए इक्विटी मालिक इसका लाभ उठाते हैं, यदि जोखिम चुकता हो जाता है और यदि जोखिम विफल हो जाता है, तो लागत जमाकर्ताओं, बॉण्डधारकों और/या करदाताओं द्वारा वहन की जाएगी। फॉरबीयरेंस आगे चलकर इक्विटी मालिकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत ऋण के

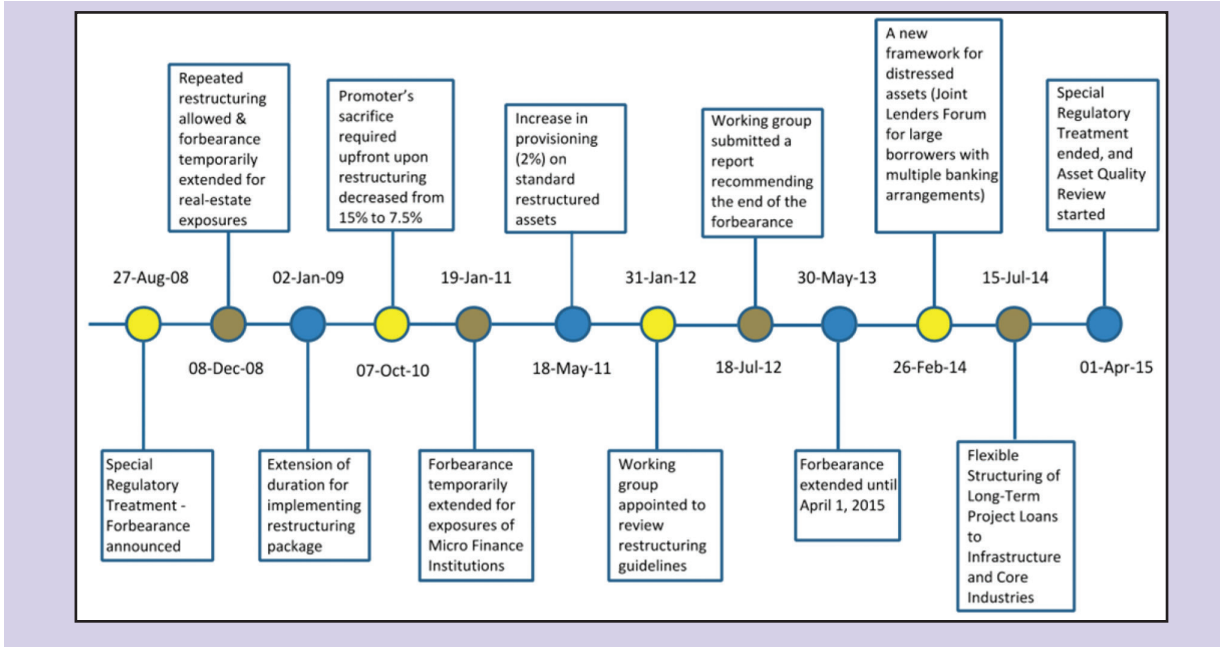
पुनर्गठन की अनुमति देती है। इसलिए फॉरबीयर्स रिजिम के अंतर्गत जब अवसर सृजित होते हैं तो कम पूंजी वाले बैंक अव्यवहार्य परियोजनाओं के लिए भी पुनर्गठन करने का चयन करते हैं जिसके कारण इक्विटी धारकों से लेकर जमाकर्ताओं और करदाताओं तक से जोखिम दूर होता है।

उपर्युक्त रियायत-प्रेरित-जोखिम स्थानांतरण का संदर्भ निजी तौर पर बैंको द्वारा रखे गए मामलों में परिलक्षित होती है, जहां इक्विटी मालिक उनके अपने हितों में कार्य कर सकते हैं। कुछ भारतीय बैंकों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयर धारिता और/या प्रबंधन अधिकारों के आधार पर, संरक्षक प्रबंध और निर्णय लेने का प्रावधान करते हैं, अपने हितों को नियंत्रित कर फॉरबीयर्स की उपस्थिति में प्रमोटर-प्रबंधक पहल के प्रोत्साहन को समझने योग्य होते हैं। हालांकि, अधिकतर भारतीय बैंक, सरकार के अधीन या उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा इसलिए, उनके अवलंबी प्रबंधकों का इन संस्थानों की कोई बड़ा हित नहीं होता। फॉरबीयर्स बैंकों के प्रोत्साहन को कैसे रोकती हैं, इस संदर्भ में, इसीलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसके औचित्य में दो प्रमुख बिन्दु शामिल हैं। पहला, उनकी व्यक्तिगत वृत्तिक चिंताओं से जुड़ा है। अवलम्बी बैंक प्रबंधकों को सदैव अपने कार्यकाल के दौरान अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सरकार, सुब्रमण्यम और तन्त्री, 2019 दर्शाते हैं कि बैंकों के अध्यक्षों को (सीईओ), सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले लाभ जैसे कि भविष्य में कॉर्पोरेट बोर्ड की सदस्यता, उनके कार्यकाल के दौरान विकृत अभ्यासों से सम्बन्धित होता है। फॉरबीयर्स इन अवलंबी प्रबंधकों को अपनी बही-खातों को दुरुस्त करने के लिए और उनके कार्यकाल के दौरान अच्छा कार्य निष्पादन दिखाने के लिए अवसर प्रदान करती है और इसलिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके वृत्तिक लाभों को बढ़ाया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि बैंक प्रबंधक फॉरबीयर्स का अनुचित लाभ उठाते हैं। दूसरा बैंकों के प्रबंधक भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए फॉरबीयर्स का एक कवच के रूप में प्रयोग करते हैं।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुई घटनाएं या पूर्व बैंक अध्यक्षों के विरुद्ध छल के हालिया आरोप इस प्रकार की सम्भावनाओं को पुष्ट करते हैं। ध्यान दें कि फॉरबीयर्स नुकसान की पहचान में देरी करके खराब ऋणों को छिपाने की अनुमति देती है। इसलिए बैंक प्रबंधक त्वरित व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए, जुड़े हुए पक्षों को अनुचित ऋण देने में बहुत कम उलटफेर करते हैं।

बाक्स 2: विनियामक फॉरबीयर्स प्रावधान

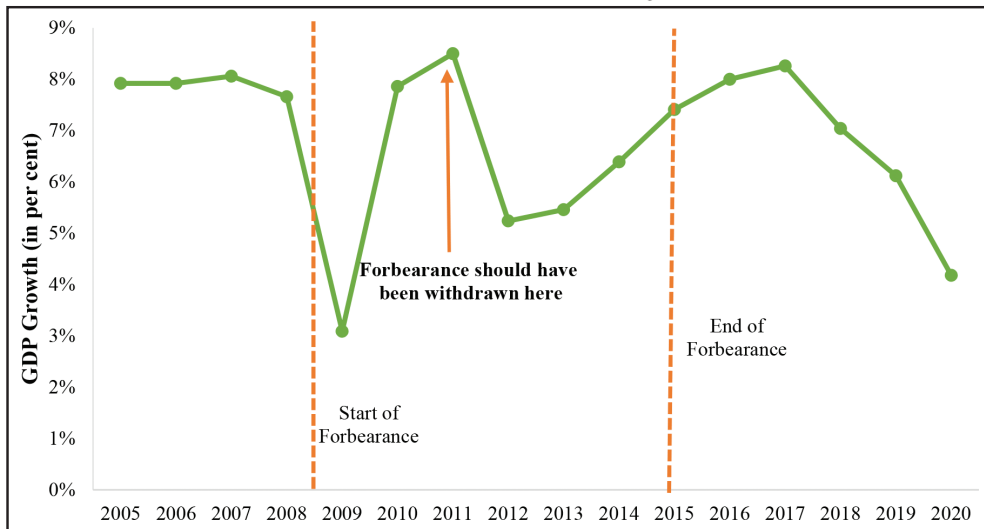
1. अगस्त, 2008 से पूर्व, प्रचलित नियमानुसार, गैर-औद्योगिक, गैर एस एम ई खातों को “मानक आस्तियों” के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिन्हें पुनर्गठित करके “उप-मानक आस्तियों” के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। कुछ शर्तों के अधीन, नए शिथिल मानकों ने उधारकर्ताओं को पुनर्गठन होने के बाद भी पूर्व वाले वर्गीकृत आस्तियों को बनाए रखा।
2. चूंकि खातों को पुनर्गठन पर उप-मानक रूप में वर्गीकृत करना जरूरी नहीं रह गया था, इसलिए बैंकों को अब वैकल्पिक आस्तियों के लिए कुल बकाया पर सामान्य प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।
3. पहले से पुनर्गठित ऋणों पर भी शिथिल मानकों को लागू किया गया। ध्यान दें 2008 से पूर्व, ऐसे ऋणों का ही पुनर्गठन किया जाता था, जिनका पुनर्गठन पहले नहीं हुआ हो। नीचे 2008-2015 की फॉरबीयर्स व्यवस्था से सम्बन्धित घोषणाओं की समय-सारणी दी गई है।



मूल पाप: सात वर्षीय फॉरबीयरेंस

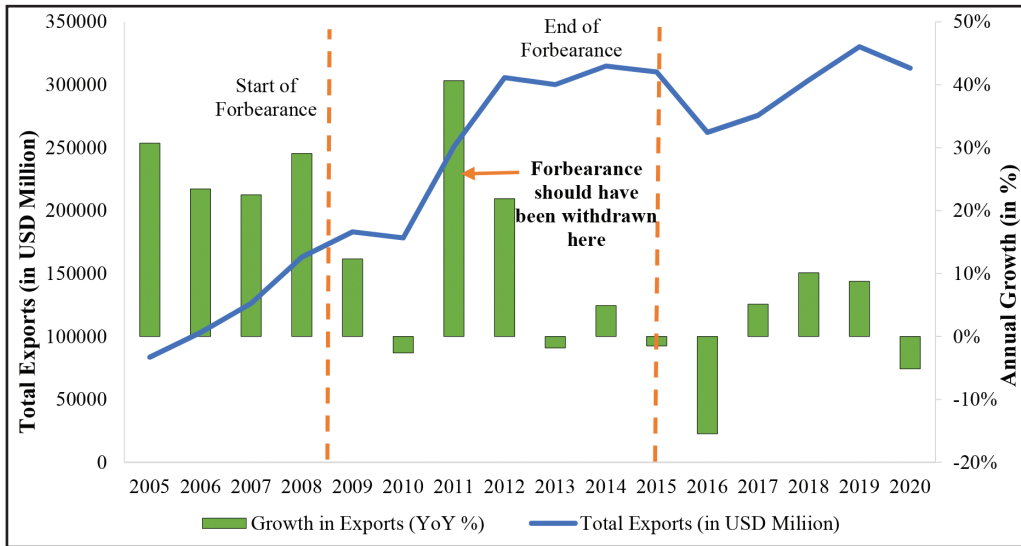
7.2 फॉरबीयरेंस नीतियां अल्पकालिक आर्थिक प्रभावों को आवश्यक बनाती है। जैसा कि चित्र-1 में दिखाया गया है जैसा कि चित्र-5 में दर्शाया गया है बैंक ऋण में वृद्धि, जो वित्त वर्ष 2008 में 23.3% से वित्त वर्ष 2010 में 16.9% तक की गिरावट आई थी वित्त वर्ष 2011 में 21.5% तक तेजी से संभल गई। जैसा कि चित्र-2 में दर्शाया गया है, जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2009 में 3.1% की कमी से दो वर्षों के भीतर ही में 8.5% तक संभल गई। औद्योगिक उत्पादन के इण्डेक्स से निर्यात तक अन्य आर्थिक संकेतक रेकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जैसाकि चित्र-2 और 3 में दर्शाया गया है। चित्र-4 से मालूम होता है कि सूचीबद्ध फर्मों की कुल आय में वृद्धि भी 2011 में 20% से अधिक के उच्च स्तर पर रही। संकट के दौरान 4.88% से कम से उबरकर यह वह समय था जब रियायतों को रोकना पड़ा था। इसके बाद भी आर्थिक हालात सुधारने में, आपातकालीन उपायों (रियायतों) ने काम किया। हालांकि केन्द्रीय बैंकों ने इसे जारी रखा। जैसा कि बाक्स-2 में दर्शाया गया है रियायतें तब भी 2015 तक पांच वर्षों के लिए जारी रही जबकि उन्हें वापिस लेने की अनुशंसा की गई थी तो यह आपातकालीन उपायों को मुख्य उपाय बनाने का एक स्पष्ट मामला था।

चित्र-1: वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर



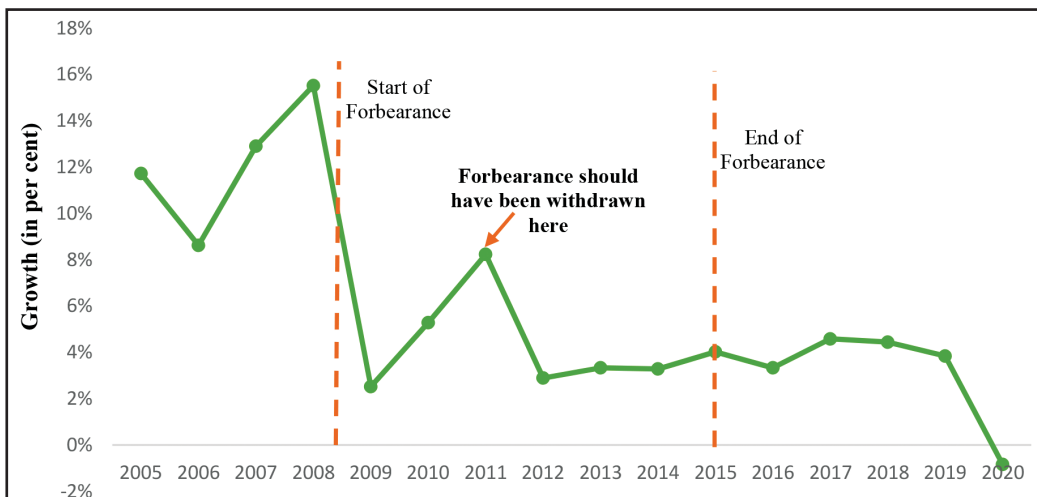
स्रोत: एनएसओ

चित्र-2: निर्यात में वृद्धि



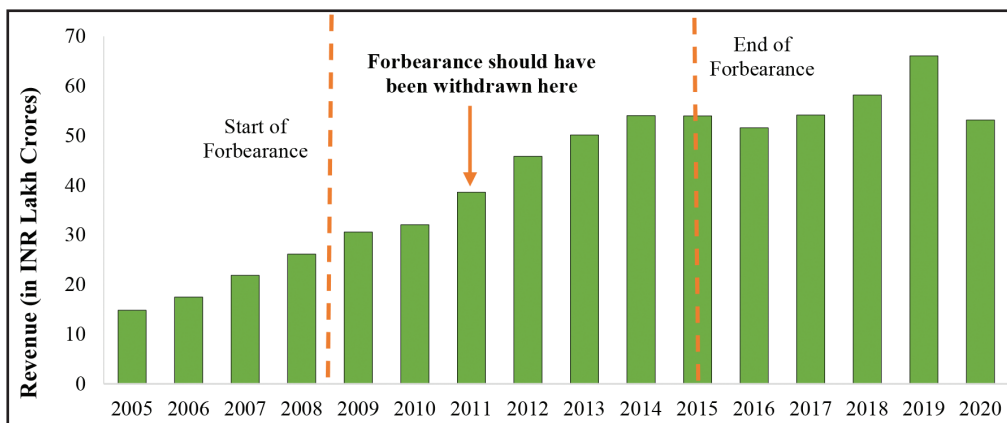
स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र-3: आयात में वृद्धि



स्रोत: वाणिज्य विभाग

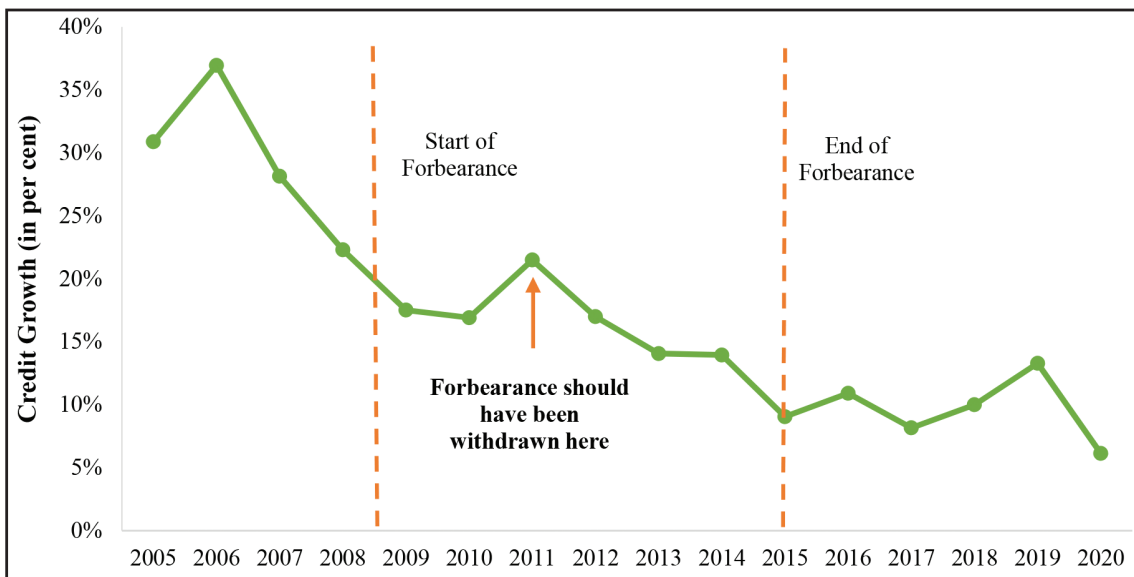
चित्र-4: औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि (आईआईपी)



स्रोत: एनएसओ।

स्रोत: कोरपोरेट व्यापार मामलों के मंत्रालय

चित्र-5: फर्म आय खरीददार हेल्थ की प्रोक्सी के रूप में।



स्रोत: कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

7.3 वैश्विक वित्तीय संकटों की अवधि के दौरान नीति ने पुनर्गठन के लिए उधारकर्ताओं की सही विपत्तियों का चयन करने में अच्छा कार्य किया परन्तु यह दीर्घ-कालिक के लिए व्यवहार्य था। बाक्स-3 भटकाने वाले विभिन्न कारकों को नियंत्रित करने के लिए केयरफुल पैनल रिगेशन के उपयोग को दर्शाता है। इसके परिणामों से मालूम होता है कि जी.एफ.सी. के दौरान, फॉरबीयरेंस से अधिकाधिक लाभ उठाने वाले बैंक, रियायतों से कमतर लाभ उठाने वाले बैंकों की तुलना में, पुनर्गठन के अपने चुनावों में बिल्कुल भी भिन्न नहीं थे। किसी भी उधारकर्ता की पुनर्गठन करने की प्रवृत्ति, अव्यवहार्य सहित, संकट के बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। जाहिर है कि एक बार जब बैंकों को आर्थिक सुधार के बावजूद, फॉरबीयरेंस के बारे में संकेत मिला तो कई तरह की विकृतियां सामने आईं हैं। जैसाकि पहले भी इंगित किया गया है, कि कभी भी आपातकालीन उपायों को मुख्य उपाय नहीं बनाना चाहिए। उदाहरणार्थ, चित्र-6 और 7 दर्शाते हैं कि ऋण पुनर्गठन के अनुपात में इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई है। पुनर्गठित ऋणों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2008 में 0.74% से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 6.94% हो गई जैसाकि चित्र-6 में दर्शाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पुनर्गठित ऋणों की हिस्सेदारी 0.82% से 8.49% से अत्यधिक थी। हालांकि, निजी क्षेत्र के बैंकों ने पुनर्गठन ऋण की अपनी हिस्सेदारी 0.64% से 2.87% तक ही बढ़ायी। इसके विपरीत जैसा कि चित्र-8 में दर्शाया गया है, रिपोर्ट को किए गए बैंकों का एनपीए वित्त वर्ष 2008 में 2.2% से मामूली सा बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 4.3% हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकों ने ऐसे ऋणों के पुनर्गठन का विकल्प इस्तेमाल किया जो ऐसे ऋणों की व्यवहार्यता की परवाह किए बिना चूक करने की कगार पर थे, जैसाकि आगे के खण्ड 8.27 में दिखाया गया है। फॉरबीयरेंस के अवसर के दौरान चूककर्ता फर्मों का अनुपात उनके ऋण/ऋणों के पुनर्गठन के बाद 51% प्रतिशत बढ़ गया। पूर्व फॉरबीयरेंस वर्षों में, पुनर्गठन के बाद चूक की संभावना में 6% की मामूली वृद्धि हुई थी। इस प्रकार फॉरबीयरेंस ने बैंकों को बहुत सारे खराब ऋणों को छिपाने में मदद की।

बाँक्स 3: बैंकों के प्रोत्साहन में विरूपण को दर्शाने के लिए डिफरेंस-इन-डिफरेंस फ्रेम वर्क

उधार प्रेरित फॉरबीयरेंस कब और कैसे बैंकों में विरूपित लगती है, का परीक्षण करने के लिए मन्नील, निशेष एवं तन्त्री (2020) डिफरेंस-इन-डिफरेंस पद्धति का प्रयोग करते हैं। यह रणनीति बैंकों द्वारा ऋण देने उन

गतिविधियों का अनुमान लगाती है जब फॉरबीयरेंस परिदृश्य में उपलब्ध नहीं होगी। फॉरबीयरेंस के उपस्थिति में वास्तविक ऋण क्रियाकलाप में डिफरेन्स तथा दूसरा डिफरेन्स, फॉरबीयरेंस के परिणामस्वरूप उपजा परिदृश्य है। इस प्रकार बैंकों को दो अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है-बी-1 और बी-2, ये दोनों बैंक बाकी सभी तरह से समान हैं, केवल फॉरबीयरेंस नीति का दोहन करने के उनकी संवेदनशीलता को छोड़कर। संक्षेप में, बी-1 वाले बैंकों का ऐसे उधारकर्ताओं का अनुपात अधिक है, जो संकट से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह स्वाभाविक रूप से बी-1 की संभावना को उनसे अधिक बढ़ाता है, जो अपेक्षाकृत रूप से विनियामक फॉरबीयरेंस सुरक्षा उपायों के प्रयोग का शोषण करते हैं। स्वामित्व, पूंजी, एनपीए और आय जैसे गुणों की तुलना के माध्यम से, मन्नील, निशेष और तंत्री (2020) दिखाते हैं कि बैंकों की बनाई गई दोनों श्रेणियां अन्यथा समान है। बी1 के बैंकों में, औसतन, ऐसे बैंक होंगे जिनकी संकट के दौरान पुनर्गठित ऋणों की हिस्सेदारी अधिक होगी क्योंकि उनके उधारकर्ताओं द्वारा संकट का अधिक सामना किया गया है। इसलिए बी-1 और बी-2 के कुल प्रतिफलों की तुलना यह समझने के लिए उचित नहीं होगी कि फॉरबीयरेंस विरूपण लाती है। इसी तरह, मन्नील, निशेष व तंत्री (2020) फर्म-लेवल फिक्सड इफेक्ट एस्टीमेट का प्रयोग करते हैं जो फर्मों और दोनों प्रकार के बैंकों के बीच में प्रतिफलों की तुलना करती है। यदि एक ही फर्म के लिए, बी-1 बैंक रियायत के दौरान एक उच्च पुनर्गठन गतिविधि का प्रदर्शन करते हैं, आश्चर्य यह है कि ये बैंक औसतन पुनर्गठन का चयन करने में अपेक्षाकृत कम विवेकपूर्ण हैं, और अप्रभावी परियोजनाओं के पुनर्गठन की भी संभावना रखते हैं क्योंकि बी-1 और बी-2 अन्यथा समान है, पुनर्गठन के लिए उनकी पद्धति में फॉरबीयरेंस को किसी भी अंतर को उनकी बदलती संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कारण-प्रभाव की पहचान के लिए इस रणनीति के साथ 2002-2015 के दौरान बैंकों की ऋण गतिविधि का विश्लेषण किया गया है। वर्ष को तीन भागों में विभाजित किया गया है-रियायत पूर्व वर्ष-2002-2008, 2009-2011 का संकट काल तथा संकट के बाद का साल 2011-2015। फर्म-बैंक-वर्ष पर आंकड़ों का संगठन, निम्नलिखित अनुमान-रिग्रेशन का है।

$$Restructured\ Loan\ Amount_{ijt} = \alpha + \beta_1 \times Treatment_j \times Crisis_t + \beta_2 \times Treatment_j \times PostCrisis_t + \beta_3 \times X_{it} + \delta_{it} + v_j + \epsilon_{ijt}$$

VARIABLES	(1)	(2)
	Restructured Loan Amount (in INR Million)	
Treatment X Crisis (2009-2011)	9.070 (12.952)	10.130 (13.675)
Treatment X Post-Crisis (2012-2015)	34.582** (16.735)	35.952** (17.642)
Bank Controls	No	Yes
Observations	237,690	237,690
R-squared	0.183	0.183
(Firm, Year) Fixed Effects	Yes	Yes
Bank Fixed Effects	Yes	Yes

सारणी-1: यह सारणी उपर्युक्त समीकरण में डिफरेंस इन डिफरेंस के अनुमानों को दर्शाता है। पुनर्गठन ऋण राशि बैंक द्वारा पुनर्गठित ऋण की कुल राशि को मापता है। पुनर्निवेशित ऋण की राशि वर्ष t में उधारकर्ता i के लिए j बैंक द्वारा पुनर्निवेशित ऋण की कुल राशि की गणना करती है। उपचार एक संकेतक वैरिएबल है जो उन बैंकों के लिए 1 का मान होता है जिनके पास मध्यम से अधिक जोखिम वाले उधारकर्ता होते हैं अन्यथा शून्य मान होता है। क्राइसेस (पोस्ट-क्राइसेस) एक और अन्य संकेतक (वैरिएबल) है जिसका वर्ष 2009-2011 (2012-2015) के लिए 1 मान होता है और अन्यथा शून्य का मान होता है। जिसको कॉलम 2 में शामिल किया जाता है जो बैंक-विशिष्ट समय परिवर्तनीय नियंत्रणों को संदर्भित

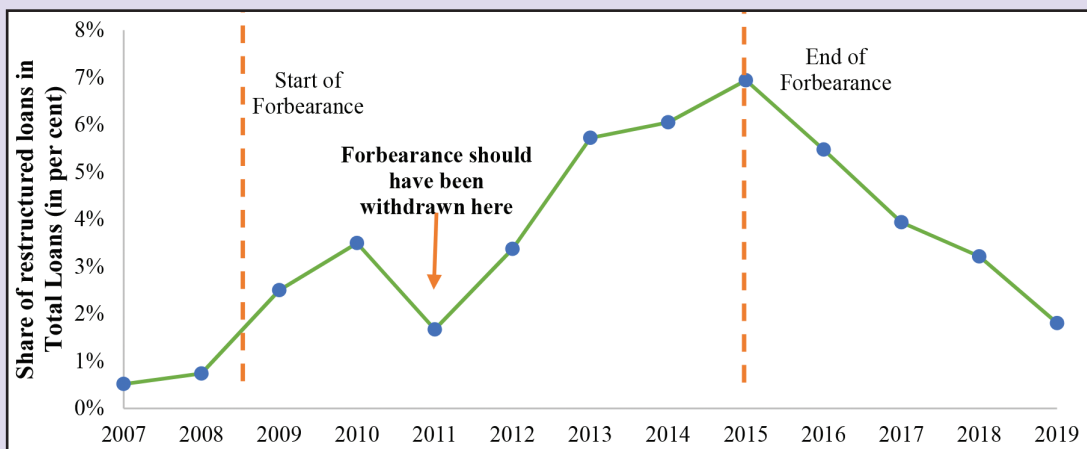
करता है, अर्थात बैंक में सरकारी स्वामित्व का भाग, विदेशी संस्थागत स्वामित्व का भाग और सीईओ का कार्यकाल। जिससे तात्पर्य है (फर्म, वर्ष)। निश्चित प्रभाव जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पुनर्गठन गतिविधि की तुलना एक (फर्म, वर्ष) के अन्तर्गत की जाती है। VJ बैंक के निश्चित प्रभाव को दर्शाता है जिसके द्वारा बैंकों में परिवर्तनों को अवशोषित किया जाता है।

*सांख्यिकीय महत्व के 5% स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। कोष्ठक में बैंक स्तर पर मानक त्रुटियां बताई गई हैं।

स्रोत: मन्लिल, निशेष और तंत्री (2020)

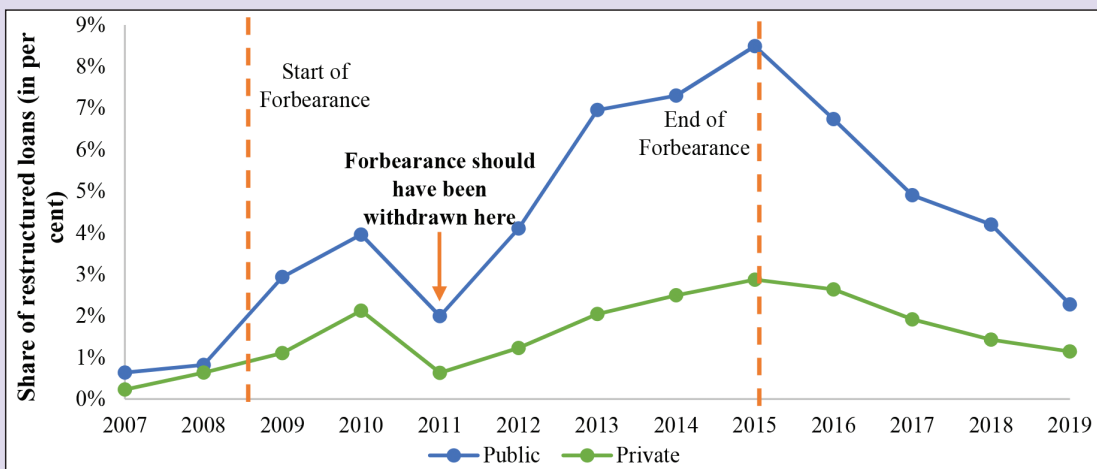
गुणांक दो प्रकार के बैंकों के बीच पूर्व फॉरबीयरेंस अवधि (2002-08) की तुलना में पुनर्गठन राशि में औसत अंतर को दर्शाता है। गुणांक क्राइसेस काल (2009-11) के दौरान शून्य से सांख्यिकीय रूप से पृथक नहीं किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि दो प्रकार के बैंकों द्वारा पुनर्गठन गतिविधि क्राइसेस के समय भिन्न नहीं होती है। ध्यान दें कि कुल पुनर्गठन की तुलना करने के बजाय, फ्रेमवर्क पुनर्गठन दी गई फर्म से विपरीततः तुलना करता है। अतः क्राइसेस के समय व्यवधान के कोई संकेत नहीं हैं। हालांकि गुणांक, 5% के सांख्यिकीय महत्व के साथ क्राइसेस के बाद की अवधि में सकारात्मक हो जाता है। यह इंगित करता है कि बैंकों द्वारा ऋण के उपयोग की संभावना अधिक होने के कारण पुनर्संरचना के लिए फर्म के चयन में सुधार हो गया। इस प्रकार क्राइसेस के अंत में लंबे समय तक फॉरबीयरेंस की प्रवृत्ति ने बैंकों को प्रोत्साहित करने को बाधित कर दिया है।

चित्र 6: पूर्वाभास के दौरान उच्चतर पुनर्गठन



स्रोत: पुनर्गठन के अध्यधीन ऋण पर आरबीआई एसटीआरबीआई तालिका संख्या 13

चित्र 7: पीएसबी द्वारा उच्चतर पुनर्गठन

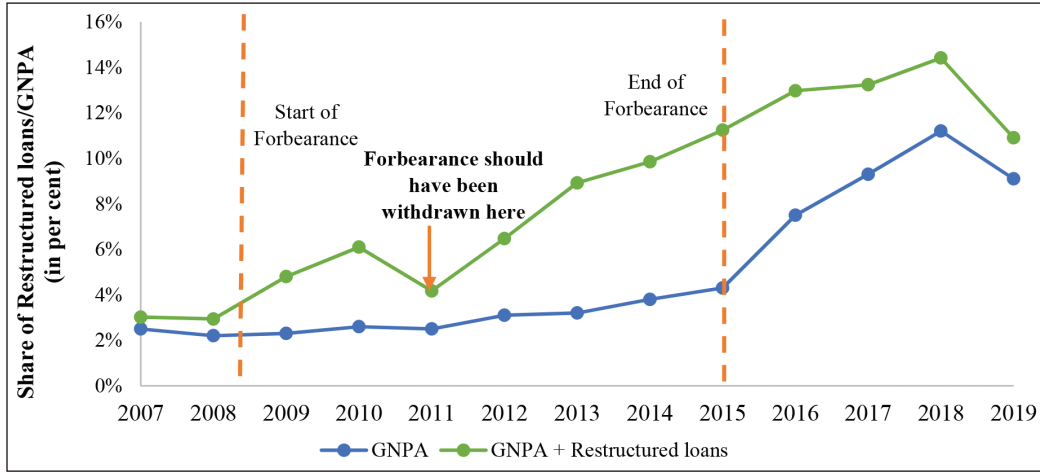


स्रोत: पुनर्गठन के अध्यधीन ऋण पर आरबीआई एसटीआरबीआई तालिका संख्या 13

सार्वजनिक: सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल ऋणों के हिस्से के रूप में पुनर्गठित ऋण।

निजी: निजी क्षेत्र के अनुसूचित सार्वजनिक बैंकों के लिए कुल ऋणों के हिस्से के रूप में पुनर्गठित ऋण।

चित्र 8: सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ और पुनर्गठित ऋण



स्रोत: एससीबी के सकल और निवल एनपीए पर आरबीआई एसटीआरबीआई तालिका 58

जीएनपीए: कुल ऋण की हिस्सेदारी के रूप में सकल एनपीए

जीएनपीए+पुनर्गठित ऋण: कुल ऋणों के हिस्से के रूप में सकल एनपीए और पुनर्गठित ऋण की राशि

7.4 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित पी.जे. नायक समिति (2014) ने मई 2014 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला था कि पुनर्वित्त व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली दोहरी चिंताएं: एनपीए को पुनर्गठित संपत्ति और बैंकों के अवपूंजीकरण के रूप में वर्गीकृत करके ऋणों को बनाए रखेगी। उदाहरण के लिए यह कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए “मौजूदा टियर-1 पूंजी विनियामक फॉरबीयरेंस छूट/प्रविरत के कारण ओवरस्टेट हो गई है जो आरबीआई पुनर्गठित परिसंपत्तियों पर प्रदान करता है। बिना फॉरबीयरेंस छूट के इन परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह पुनर्गठन की एक प्रतिक्रिया होने के कारण बड़ी चूक हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान बढ़ेगा और टियर-1 पूंजी घट जाएगी।” इस प्रकार कई बैंकों की फॉरबीयरेंस अवधि के दौरान कम पूंजी थी। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि यदि मई 2014 में विनियामक छूट तुरंत वापस ले ली जाए और पुनर्गठन परिसंपत्तियों के लिए विवेकपूर्ण 70% प्रावधान कवर प्रदान किया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की टियर-1 पूंजी 2.78 लाख करोड़ रुपये कम हो जाएगी। जैसा कि हमने बाद के भाग 8.6-8.8 में उजागर किया है कि बैंकिंग क्राइसेस का शीघ्र निपटान हो जाने से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को सीमित करता है। फिर भी आरबीआई ने बैंकों को यह समझाने की कोशिश छोड़ दी, कि एनपीए और पुनर्गठित परिसंपत्तियों के मध्य अन्तर केवल चतुर्थाई से किया गया लेखांकन है (राजन 2014 पीपी 4)। इसके परिणामस्वरूप स्थिति और अधिक बिगड़ गई।

7.5 2015 में रियायत छूट की नीति को समाप्त किए जाने पर आर बी आई ने परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की थी ताकि यह पता किया जा सके कि बैंकिंग प्रणाली में अशोध्य ऋण की वास्तविक राशि क्या है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों ने उजागर किया कि 2014-2015 से 2015-16 तक एनपीए में अधिक बढ़ोत्तरी हुई थी। फॉरबीयरेंस की अनुपस्थिति में बैंकों ने ऋणों को पुनर्गठित करने हेतु एनपीए दर्शाना ठीक समझा। अतः वर्तमान में हो रहे बैंकिंग क्राइसेस की जड़ें 2008 से 2015 के मध्य में अपनाई लंबी अवधि की फॉरबीयरेंस नीति से संबद्ध है।

विस्तारित फॉरबीयरेंस की लागत बनाम बैंकिंग क्राइसेस का शीघ्र समाधान: अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य

7.6 जी-20 देशों में समय के साथ गैर-निष्पादित ऋणों के क्रमिक विस्तार का पैमाना, विस्तारित फॉरबीयरेंस की लागतों बनाम बैंकिंग संकट के शीघ्र समाधान पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस उद्देश्य से वैश्विक

वित्तीय संकट का पता लगने के पश्चात् उस वर्ष देश में एनपीए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 2009 और 2010 (2009-2010) के दौरान एनपीए के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले देशों को “शीघ्र समाधानकर्ता” (“अर्ली रिजॉल्वर”) के रूप में जाना जाता है। इन देशों ने अतिशीघ्र अशोध्य ऋण की समस्या को पहचान लिया, और इसके समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए। 2009-10 के पश्चात् गैर निष्पादित ऋणों की हिस्सेदारी में कमी आना शुरू हो गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं जिन्होंने अनुपयोगी आस्तियों की पहचान त्वरित रूप में करते हुए पुनः पूंजीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी।

7.7 इसके विपरीत, “लेट रिजॉल्वर” उन देशों के अनुरूप थे जो 2015-19 में अपने चरम एनपीए पर पहुंच गए थे, यानि क्राइसेस के एक दशक के बाद तक। जैसा कि भारत के मामले में बताया गया है, जहां विनियामक रियायत नीति से बैंकों को वास्तविक एनपीए की पहचान करने में विलम्ब हुआ और अशोध्य खराब ऋण का समाधान शीघ्र न हो पाने से क्राइसेस बहुत वर्षों के बाद भी समाप्त नहीं हो पाया। “अर्ली रिजॉल्वर” और “लेट रिजॉल्वर” के मध्य कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

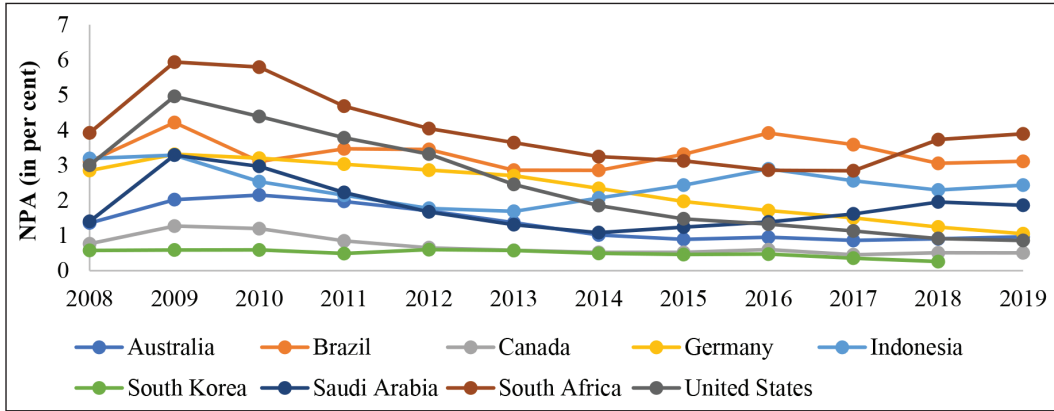
7.8 जैसा कि तालिका 2 और चित्र 9-10 में देखा गया है कि “लेट रिजॉल्वर” “अर्ली रिजॉल्वर” की तुलना में एनपीए के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। वास्तव में औसतन लेट रिजॉल्वर के एनपीए “अर्ली रिजॉल्वर” से तीन गुना थे (चित्र 11)। दूसरी ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि लेट रिजॉल्वर (औसतन -1.7%) के लिए जीडीपी वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव अर्ली रिजॉल्वर की तुलना में बहुत खराब (औसतन -0.8%) थे जैसा कि तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2: देशों का एनपीए अनुपात और इनका वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् उच्चतम स्तर पर पहुंचना।

अर्ली रिजॉल्वर (2009-2010)		लेट रिजॉल्वर (2015-2019)	
परिसंपत्ति पर उच्चतम एनपीए % में		परिसंपत्ति पर उच्चतम एनपीए % में	
ब्राजील	4.21	अर्जेंटीना	5.75
कनाडा	1.27	चीन	2.40
जर्मनी	3.31	भारत	9.98
इंडोनेशिया	3.29	इटली	18.06
सऊदी अरब	3.29	पुर्तगल	17.48
दक्षिण अफ्रीका	5.94	रूस	10.12
संयुक्त राज्य अमेरिका	4.96	टर्की	5.02
ऑस्ट्रेलिया	2.15		
दक्षिण कोरिया	0.59		
औसत	3.22	औसत	9.83

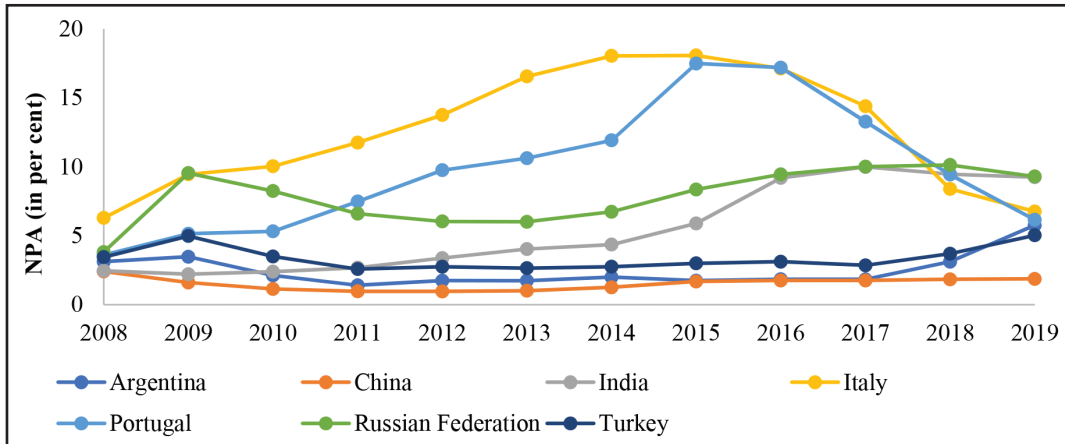
स्रोत: आई एम एफ

चित्र 9: “अर्ली रिजॉल्वर” के लिए एनपीए प्रवृत्ति (चित्र मूल से देखें)



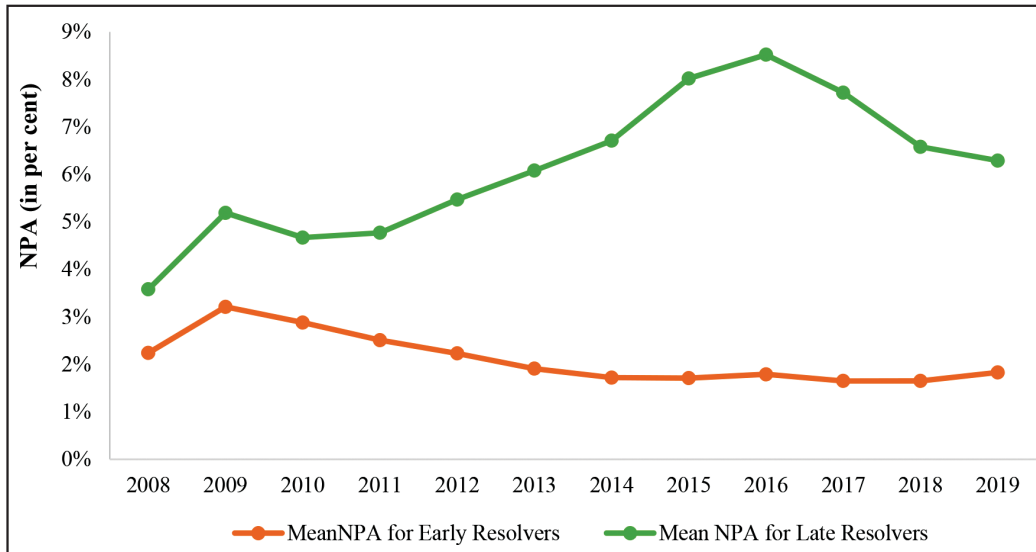
स्रोत: आई एम एफ वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

चित्र 10: “लेट रिजॉल्वर” के लिए एनपीए प्रवृत्ति



स्रोत: आईएमएफ वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

चित्र 11: अर्ली रिजॉल्वर बनाम लेट रिजॉल्वर के लिए एनपीए ट्रेंड (प्रवृत्ति)



स्रोत: आई एम एफ वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

तालिका 3 : शुरूआती रिजॉल्वर बनाम लेट रिजॉल्वर के लिए पोस्ट और प्री-क्राइसेस वाले जीडीपी में अंतर

अर्ली रिजॉल्वर	औसत जीडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)			लेट रिजॉल्वर	औसत जीडीपी वृद्धि दर प्रतिशत में		
	प्री क्राइसेस	पोस्ट क्राइसेस	अंतर		प्री क्राइसेस	पोस्ट क्राइसेस	अंतर
	1998.07	2008.19	अंतर		1998.07	2008.19	अंतर
आस्ट्रेलिया	3.59	2.53	-1.06	अर्जेंटीना	2.82	0.99	-1.83
ब्राजील	2.99	1.57	-1.42	चीन	10.01	7.97	ख़2.04
कनाडा	3.19	1.66	-1.53	भारत	7.16	6.85	-0.31
जर्मनी	1.63	1.22	-0.41	इटली	1.51	-0.32	-1.83
इंडोनेशिया	2.81	5.54	2.73	रूस	5.85	1.44	-4.41
दक्षिण कोरिया	5.18	3.08	-2.11	टर्की	4.38	4.55	0.17
सऊदी अरब	3.01	3.23	0.21	पुर्तगल	2.1	0.43	-1.68
दक्षिण अफ्रीका	3.73	1.54	-2.19				
संयुक्त राज्य अमेरिका	3.11	1.70	-1.41				
औसत	3.25	2.45	-0.80	औसत	4.83	3.13	-1.70

स्रोत: आई एम एफ

7.9 लंबी अवधि तक लागू रही रियायत नीति के निष्कर्ष को निम्नलिखित खंडों में विस्तार से बताया गया है। चर्चा को चार व्यापक खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड बैंकों के ऋण देने के तरीकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालता है, दूसरा खंड उधारकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालता है, तीसरा खंड क्लीन अप चरण की जांच करता है, और अंतिम चरण नीति लागू करवाने से संबंधित हैं।

बैंक के प्रदर्शन और ऋण देने पर मिलने वाली रियायत से पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव बैंकों का अल्पपूंजीकरण

7.10 बैंक अवैध ऋणों को नकद (लिक्विड) देनदारियों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। (डायमण्ड और डिबयग, 1983)। दूसरे शब्दों में, जब बैंक मांग पर या किसी विशिष्ट अवधि के बाद पुनर्भुगतान जमा जारी करते हैं, तो वे लंबी अवधि वाली परियोजनाओं को उधार देता है। इसलिए वे दोनों (i) अंतर्वाह और अप्रत्याशित बहिर्वाह के समय में बेमेल (लिक्विडिटी बेमेल के रूप के संदर्भित) और (ii) उधारकर्ता (डिफॉल्ट) द्वारा भुगतान न करने पर अप्रत्याशित उछाल का सामना करना पड़ता है। सामान्य चूक और नियमित बहिर्वाह की कीमत आमतौर पर नियमित परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (ए एल एम) ढांचे के भीतर प्रदान की जाती है। पूंजी एक आधार प्रदान करती है जो बैंकों को असामान्य जमाकर्ता निकासी और दी गई ऋणों पर बढ़ते घाटे के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है।

7.11 लंबी अवधि तक दी जाने वाली रियायत नीति के प्रभाव के फलस्वरूप वास्तविक पूंजी को बढ़ा कर दिखाया जाता है और इससे सुरक्षा की छद्म भावना उत्पन्न होती है। रियायत देने से पहले 12%¹ की पूंजी पर्याप्तता वाले बैंक पर विचार करें। मान लें कि (संकट) क्राइसेस के समय बैंक अपनी बहियों का 10% पुनर्गठन करता है। रियायत के न मिलने पर बैंक पुनर्गठन हेतु प्रावधान करेगा और प्रावधानों की सीमा तक पूंजी कम हो जाएगी। आगे काम करने के लिए, बैंकों को नई पूंजी जुटाकर नियामक सीमा को पूरा करना होगा। हालांकि रियायत मिलने पर बैंक वापस न किए गए ऋणों को पुनर्गठित कर सकता है, और 12% तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात को रिपोर्ट कर सकता है। इसे अलग रूप में देखा जाए तो रियायत मिलने की दशा में गैर पूंजीगत बैंक

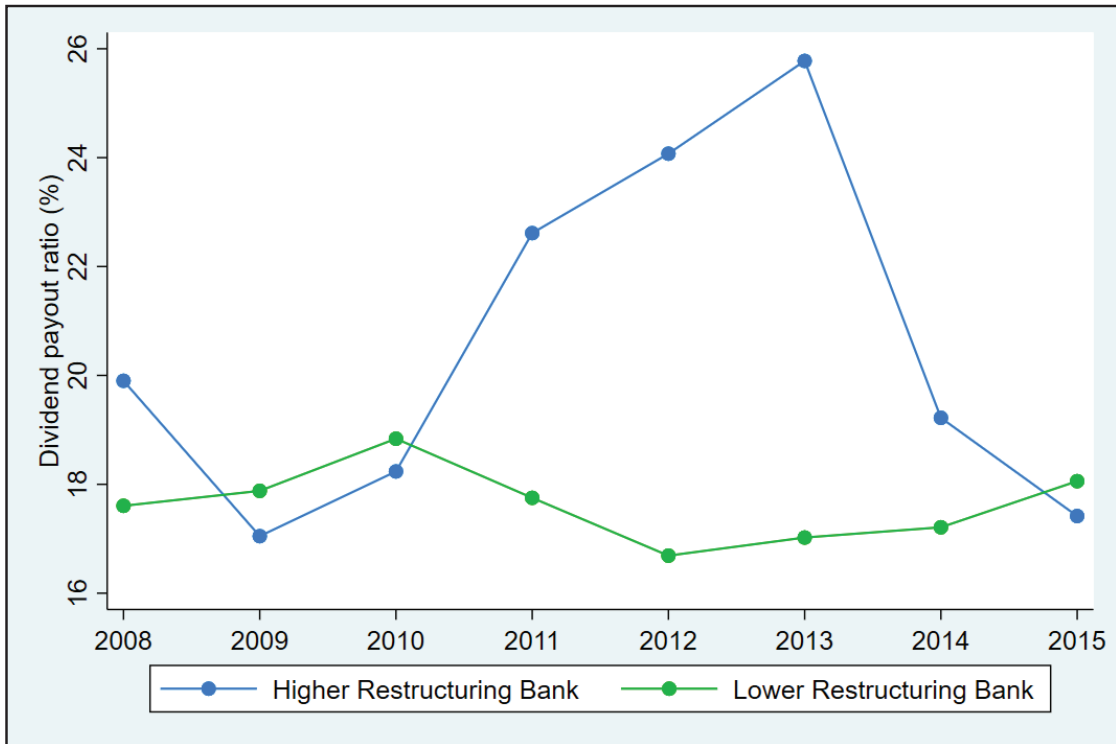
¹ भारत के बैंकों को 9% की पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है। हम वैधानिक पूंजीगत बफर के अन्य प्रकारों की उपेक्षा करते हैं, तथा यह उदाहरण केवल स्पष्टीकरण हेतु है।

पूंजी को बिना बढ़ाए कार्य कर सकते हैं। अपर्याप्त पूंजी ठीक उसी तरह से है जैसे पूंजी के न होने पर भी मालिक को सुरक्षा का अनुभव होना। मायर्स (1976) से शुरू होने वाले वित्त के एक लंबे साहित्य, में किसी भी संगठन को चलाने वाले के पास अपर्याप्त “पूंजी की सुरक्षा”/ (“स्कन इन द गेम”) होने की दशा में पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की है।

7.12 कई निहितार्थ का पालन करते हैं। प्रथम, चूंकि इक्विटी पूंजी बैंकों के मालिकों के लिए निजी रूप से महंगी है, इसलिए बैंक अपनी पूंजी को वापस लेने के लिए मिलने वाली छूट का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऊपर दिए गए चित्रण में बैंक लाभकारी पूंजी के आंकड़े की रिपोर्टिंग कर सकता है जबकि बिना छूट के सही संख्या विनियामक सीमा से कम हो सकती है। अगर छूट की अवधि बढ़ाई जाती है, तो बैंक विनियामक से ऊपर की पूंजी को “अतिरिक्त” पूंजी के रूप में मान सकता है और अवलंबी मालिकों को लाभांश के रूप में पूंजी चुकाना पड़ सकता है (मन्निल, निशेश और तंत्री 2020)। इस प्रकार वित्त का सामान्य पैकिंग ऑर्डर (मायर्स 1977), मोदिग्लिआनी और मिलर (1958) है, जहां इक्विटी से पहले चुकाया गया ऋण वापस कर दिया जाता है। आखिरकार जब छूट वापस ली जाती है तो, जमाकर्ता या करदाताओं को बिल जमा करने के लिए कहा जाता है।

7.13 ऊपर वर्णित घटना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मिलने वाली रियायतों के दौरान घटित हुई। छूट से लाभान्वित होने वाले बैंकों ने अपने लाभांश के भुगतान को बढ़ाकर सरकार एवं प्रबंधन पदाधिकारी तक सीमित कर दिया है। जैसा कि चित्र 12 में देखा गया है कि पुनर्गठित ऋणों की कम हिस्सेदारी वाले बैंकों के साथ पुनर्गठित ऋणों की उच्च हिस्सेदारी वाले बैंकों के मध्य 2012-13 के दौरान अनुपात अधिकतम 9% था।

चित्र 12 : बैंकों द्वारा लाभांश भुगतान



स्रोत: सी एम आई ई कौशल

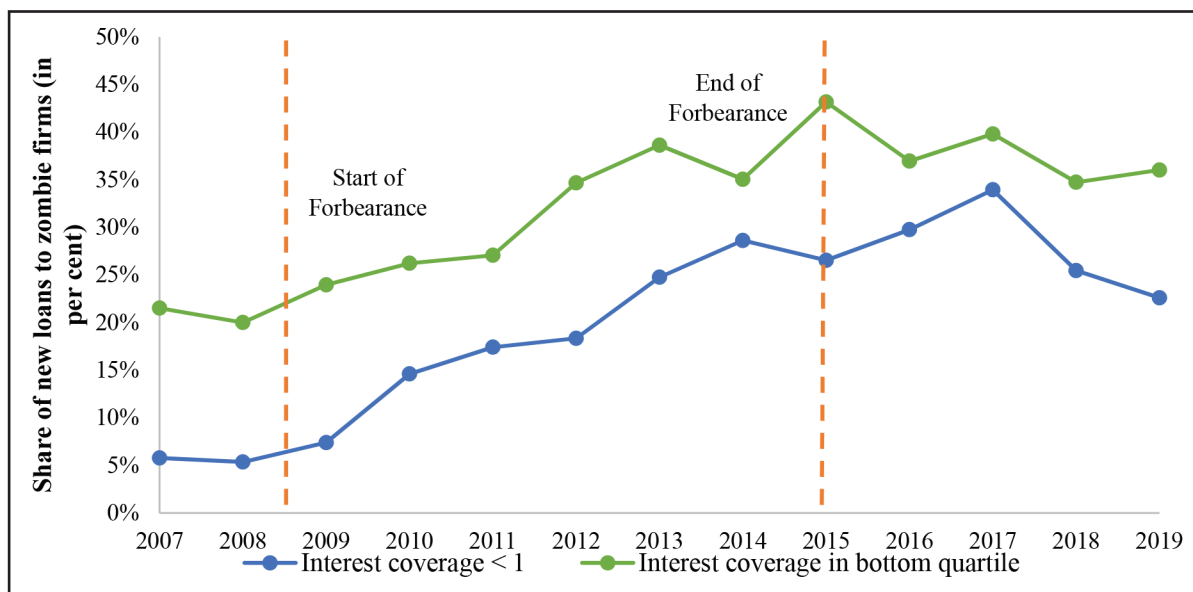
उच्च (निम्न) पुनर्गठन बैंक: पुनर्गठित ऋणों के ऊपरी-मध्य (निचला-मध्य) शेयर वाले बैंकों द्वारा औसत लाभांश भुगतान।

7.14 इसके अलावा पुनर्गठित ऋणों के उच्च हिस्से वाले बैंकों ने पुनर्गठित ऋणों के कम हिस्सेदारी वाली बैंकों की तुलना में कम नई पूंजी जुटाई। उच्च हिस्सेदारी वाले बैंकों ने पूर्व में दी गई छूट के दौरान अपनी औसत परिसंपत्ति का केवल 1.67% नई पूंजी के रूप में जबकि कम हिस्सेदारी वाले बैंकों ने इस अवधि के दौरान 2.04% नई पूंजी जुटाई। उच्च पुनर्गठन वाले बैंकों द्वारा किया गया अधिक लाभांश भुगतान तथा बैंकों में कम पूंजी आने से अंतः प्रवाह में बढ़ोत्तरी हुई है। उच्च लाभांश और कम नई पूंजी के संयुक्त प्रभाव के कारण दोनों प्रकार के बैंकों के बीच पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) में काफी अंतर आया। 2014-15 में कम पुनर्गठित परिसंपत्तियों वाले बैंकों की तुलना में पुनर्गठित ऋणों की अधिक हिस्सेदारी वाले बैंकों के लिए सीएआर 2.5 प्रतिशत अंकों के करीब था। इस प्रकार छूट की नीति से कई बैंकों की पूंजी कम हो गई।

7.15 जॉबी (फर्जी) फर्मों को ऋण देना- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूंजी में कमी “ऊपरी सुरक्षा” (“स्क्रीन इन द गेम”) के समान है। यह बैंक मालिकों और अवलंबी प्रबंधक वर्ग को हतोत्साहित करता है। अपने धन में कमी होने के कारण बैंक तेजी से जोखिम लेने वाले (डायमण्ड और राजन, 2011) बन जाते हैं। जैसा कि बॉक्स 1 में बताया गया है, कम पूंजी वाले बैंक जोखिमपूर्ण उधार और गैरकानूनी ऋण देने की प्रथाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे उच्च अग्रिम शुल्क, आकर्षक योजनाएं।

7.16 चारी, जैन और कुलकर्णी (2019) दस्तावेज में कहा गया है कि विनियामक रियायत से ऋण चुकाने की कम क्षमता और निम्न-लिक्विडिटी फर्मों को ऋण देने में वृद्धि की है। संक्षेप में रियायत की अवधि में अनुत्पादक फर्मों को ऋण देने में वृद्धि देखी गई, जिसे (फर्जी फर्म) ‘जॉबी’ के रूप में जाना जाता है। जॉबी (फर्जी कम्पनी) को विशेष रूप से ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग करते हुए तथा कुल ब्याज व्यय पर लगे कर के पश्चात् फर्म को हुए लाभ के अनुपात से पहचाना जाता है। एक से कम ब्याज अनुपात वाले फर्म अपनी आय से ब्याज बाध्यताओं को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है और इसे जॉबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि चित्र 13 में दर्शाया गया है, ऐसे फर्मों पर नई ऋण की हिस्सेदारी 2007-08 में 5% से बढ़कर 2014-15 में 27% पर पहुंच गई।

चित्र 13: जॉबी उधार में वृद्धि



स्रोत: एम सी ए शुल्कों की सूची और सी एम आई ई कौशल

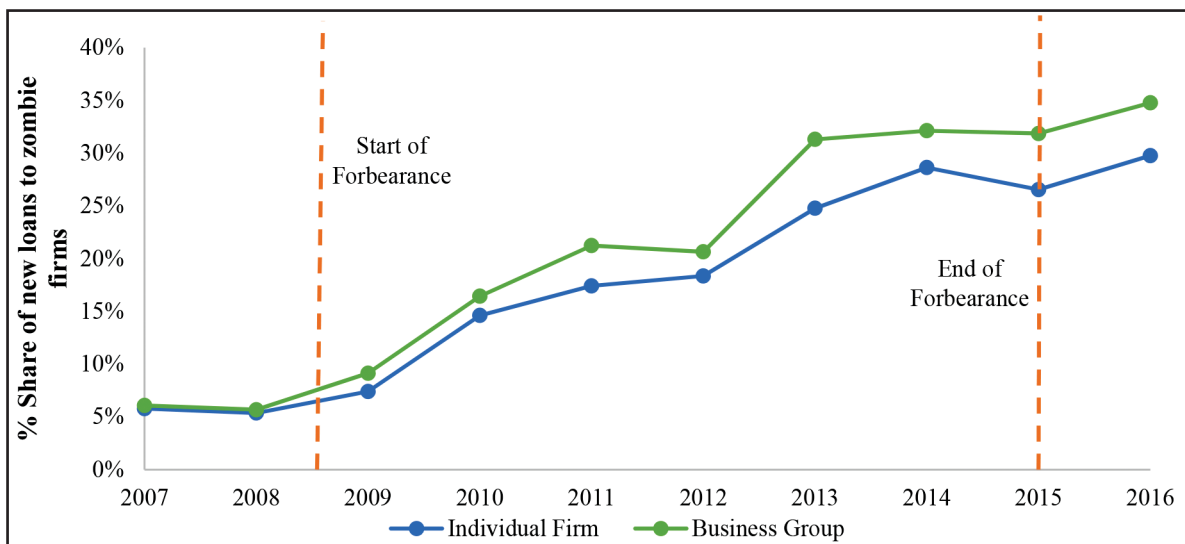
7.17 जॉंबी (फर्जी कम्पनी) को दिए गए ऋण में रियायत व्यवस्था देना खराब वित्तीय व्यवस्था का संकेतक है। यह आकलन करने के लिए कि क्या यह वास्तव में जोखिम भरा ऋण देने का मामला है, जॉंबी फर्मों की एक संशोधित परिभाषा मानी जाती है। इस वैकल्पिक परिभाषा के तहत, जॉंबी फर्म वे हैं जिनकी ब्याज कवरेज अनुपात नीचे चतुर्थक में है। यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि सभी वर्षों में जॉंबी का अनुपात समान रहे। संशोधित परिभाषा के साथ जॉंबी फर्मों को मंजूर किए गए नए ऋणों का हिस्सा 2007-08 में 20% से बढ़कर 2014-15 में 43% हो गया, जैसा कि चित्र 13 में दिखाया गया है। यह स्पष्ट रूप में बैंकों द्वारा जोखिम भरा ऋण देने में वृद्धि को दर्शाता है।

सस्ती ऋण व्यवस्था (एवरग्रीनींग ऑफ लोन)

7.18 कम पूंजी वाले बैंकों के लिए खराब गुणवत्ता वाली कंपनियों को ऋण देने का एक और मकसद है: अपने पहले से ही कमजोर पूंजी की रक्षा करना। कभी न चुकाने वाले ऋणों का एक तरीका यह है कि ऋण लेने वाले को डिफॉल्ट के कगार पर एक नया ऋण दिया जाता है, जो मौजूदा ऋण की चुकौती तिथि के पास होता है, ताकि उसके पुनर्भुगतान (तंत्री, 2020) को सुगम बनाया जा सके। ऐसे लेन-देनों का पता नहीं लग पाता, क्योंकि बैंकों को उन्हें खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि पुनर्गठन के विपरीत वॉरेंट का खुलासा करते हैं।

7.19 करस्थम उधारकर्ताओं को अपना उधार देने को छिपाने के लिए बैंक ऐसे व्यवसाय समूह में आर्थिक रूप से सुदृढ़ अन्य फर्मों को सीधे ऋण दे सकते हैं जिनसे ये उधारकर्ता संबद्ध हों। इसलिए, जॉंबी ऋण देने के अधिक पुष्ट अनुमान के लिए, किसी व्यक्तिगत फर्मों के स्थान पर उसके पूरे व्यावसायिक समूह पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है। एक व्यावसायिक समूह को एक जॉंबी के रूप में वर्गीकृत तब किया जाता है जब पूरे समूह का ब्याज कवरेज अनुपात एक अकेली फर्म से कम हो जाता है। चित्र-14 में, हरी रेखा जॉंबी व्यवसाय समूहों को ऋण देने के भाग को निरूपित कर रही है और नीले रंग की रेखा व्यक्तिगत जॉंबी फर्मों को निरूपित करती है। दो रेखाओं के बीच का अंतर एक जॉंबी व्यवसाय समूह से संबंधित एक स्वस्थ फर्म के ऋण को दर्शाता है। यह अंतर वित्त-वर्ष 2013 में अधिकतम 6% शिखर पर पहुंच गया था। इसलिए, बैंकों ने संभवतः जॉंबी फर्मों से संबंधित फर्मों को ऋण देने के उपरोक्त अप्रत्यक्ष तंत्र का उपयोग अपने विद्यमान ऋणों की चुकौती की आशा के साथ किया था। इसका साक्ष्य बॉक्स-4 में उपलब्ध करवाया गया है।

चित्र 14 : जॉंबी फर्मों को नए ऋणों का भाग



स्रोत: चार्ज (प्रभार) का कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय इंडेक्स

व्यक्तिगत फर्म: जॉंबी फर्मों के लिए नए ऋण के भाग का प्रतिशत (एक से कम ब्याज कवरेज)

बिज़नेस ग्रुप: जॉंबी बिज़नेस ग्रुप से जुड़े फर्मों को नए ऋण के भाग का प्रतिशत (बिज़नेस ग्रुप जिनका संयुक्त ब्याज कवरेज एक से कम है)

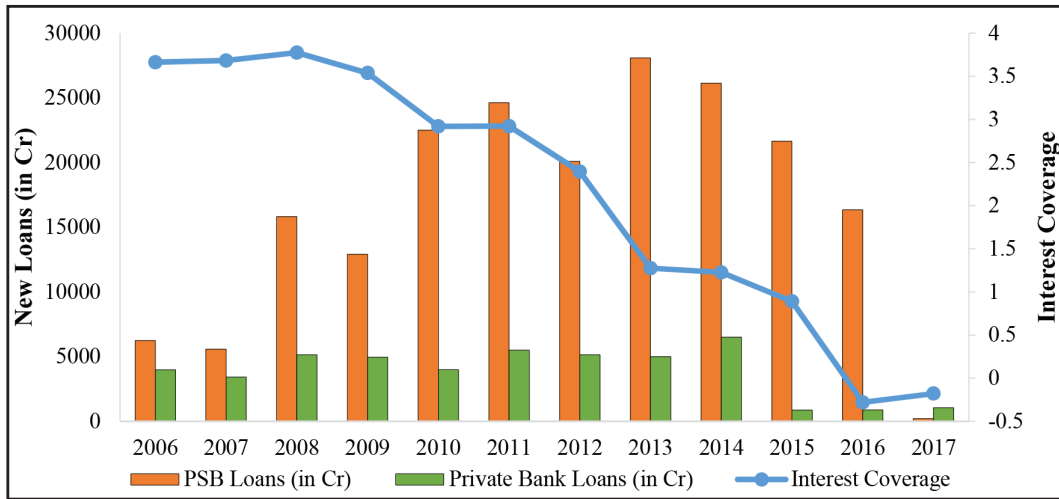
नीचे दिए गए दृष्टांत से पता चलता है कि किस तरह एक व्यापारिक समूह में वित्तीय दृष्टि से कठिनाई का सामना करने वाली फर्म प्रविरत-अवधि के दौरान समूह की अन्य फर्मों के माध्यम से किस प्रकार ऋणों को निरंतर प्राप्त करती रहती है। एक व्यावसायिक समूह में अनेक फर्में थीं, जिनमें से 4 प्रमुख फर्मों ने 2008-09 से 2014-15 की अवधि के दौरान ऋणों का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। समूह के भीतर फर्म A सबसे अधिक कठिनाई पैदा करने वाली फर्म थी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2013 के बाद से बैंकों ने ऋण देना बंद कर दिया था। फिर भी, उन्हीं बैंकों ने फर्म C को वर्धित ऋण देना जारी रखा, जिसके द्वारा फर्म A को ऋण का अतिरिक्त भाग दिया जा सकता था। समग्र व्यावसायिक समूह के पास वित्त वर्ष 2013 से लेकर वित्त वर्ष 2015 तक -0.04 का संयुक्त ब्याज कवरेज था। फर्म C ने, जिसके पास 4.41 का ब्याज कवरेज था, वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2015 के दौरान 2,244 करोड़ भारतीय रुपये मूल्य के ऋण प्राप्त किए। यद्यपि यह ऋण बैंकों की ऋण पुस्तिकाओं में स्वस्थ दिखाई देते थे, किन्तु ये एक करस्थ व्यावसायिक-समूह को दिया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक एक करस्थ समूह के स्वस्थ उधारकर्ताओं को उधार देकर परोक्षी (प्रॉक्सी) ज़ोंबी ऋण देने के काम में लगे हुए हैं, और स्वस्थ फर्म अंततः व्यावसायिक-समूह के भीतर अन्य करस्थ फर्मों को ऋण अपयोजित कर देती हैं।

फर्म का नाम	ऋण राशि (करोड़ रूपए में)				इंटरैस्ट कवरेज	
	2009-12		2013-2015		2009-12	2013-15
	पब्लिक सेक्टर बैंक	प्राइवेट	पब्लिक सेक्टर बैंक	प्राइवेट		
फर्म A	3430	267	0	0	-1.34	-1.37
फर्म B	637	835	52	12	8.51	-0.32
फर्म C	0	66	1652	592	3.85	4.41
फर्म D (2013 में बेची गई)	2381	819	150	2506	3.43	.057

बॉक्स 5: “डर्टी डजन” को उधार देना

डर्टी डजन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचानी गई वे 12 (दर्जन) बड़ी फर्म हैं जिनका 2016-17 में समग्र एनपीए का 25% योगदान था, अर्थात् 3.45 लाख करोड़ भारतीय रुपये। ये फर्म इस प्रकार हैं - भूषण स्टील, भूषण पावर, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, जेपी इंफ्रा, ईरा इंफ्रा, एमटेक ऑटो, एबीजी शिपयार्ड, ज्योति स्ट्रक्चर्स, मोनेट इस्पात, लैंको इंफ्राटेक, आलोक इंडस्ट्रीज और एस्सार स्टील। इन फर्मों ने प्रविरत माध्यम से तब भी ऋण प्राप्त करना जारी रखा जब उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी। जैसा कि नीचे चित्र-15 में देखा गया है, वर्ष 2007 से 2014 तक डर्टी डोजेन फर्मों को नए ऋण देने की बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई देती है, जबकि वित्तीय वर्ष 2007 से वित्तीय वर्ष 2015 तक औसत ब्याज कवरेज में 3.66 से 0.89 की गिरावट हो गई थी।

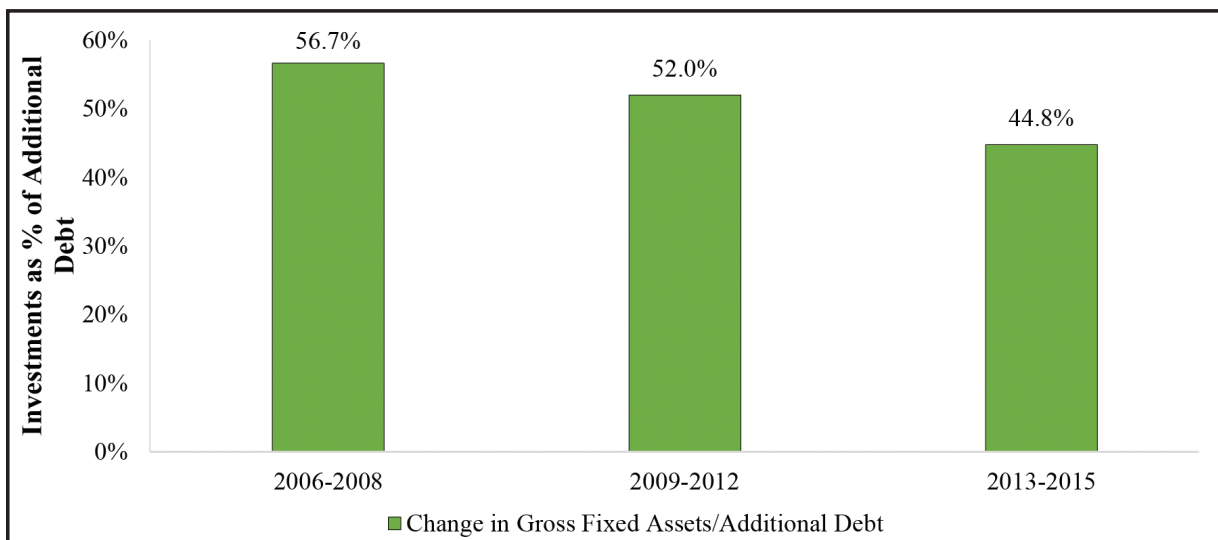
चित्र बी-1: डर्टी डजन फर्मों को दिए गए नए ऋण बनाम उनका ब्याज कवरेज



स्रोत: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

7.20 इस प्रकार के फॉरबीयरेंस परिणाम स्वरूप खराब आधार वाली फर्मों और अयोग्य परियोजनाओं को ऋण दिए जाने में वृद्धि हो गयी। फलस्वरूप, वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 तक औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ी ऋण वृद्धि उच्च निवेश दर में परिवर्तित होने में विफल हो गयी। सकल घरेलू उत्पाद में भारत का सकल फिक्स्ड केपिटल फॉर्मेशन वर्ष 2008 में 34.7% से घटकर वर्ष 2015 में 28.7% तक आ गया। गैर-वित्तीय फर्मों के भीतर, कुल अचल परिसम्पत्तियों के परिवर्धन और अतिरिक्त ऋण का अनुपात वर्ष 2005-2008 की अवधि से वर्ष 2012-2015 की अवधि तक 56.7% से घटकर 44.8% रह गया, जैसा कि चित्र-15 में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में, नए ऋणों के छोटे भाग का उपयोग पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन जैसे कि भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि के लिए किया गया था। ऐसा लगता है कि ऋण का एक बड़ा भाग एवर ग्रीनिंग के द्वारा अशोध्य ऋणों को बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया।

चित्र 15: फर्म निवेश में कमी



स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र (सी एम आई ई)

कंपनी अभिशासन के कमजोर पड़ने से उधारकर्ताओं को फॉरबीयरेंस से लाभ

7.21 जैसा कि पिछले भाग में बताया गया है, प्रविरत-अवधि में उन कॉर्पोरेट्स को पर्याप्त मात्रा में ऋण दिए गए थे जिनकी ऑपरेटिंग मेट्रिक्स कमजोर थी और इसके साथ ही उनके निवेश तथा ऋण के अनुपात में भी गिरावट आ रही थी। इससे पता चलता है कि बढ़ी हुई राशि के ऋण का उपयोग फर्मों द्वारा उत्पादकता के लिए नहीं किया गया था। चोपड़ा, निशेष और तांत्री (2020) दर्शाते हैं कि इस ऋण का अपयोजन प्रबंधन पदधारकों के निजी लाभ के लिए किया गया था। वे दावा करते हैं कि पदधारी प्रबंधक की प्रविरत-नीति के अंतर्गत पुनः स्थापन ऋण प्राप्त करने की क्षमता ने फर्म के अंदर उनके प्रभाव को बढ़ा दिया है। ऋण-पुनःसंरचना की प्रक्रिया में उन बैंकर के साथ बातचीत अवश्य होती है जिनके पास ऋण-पुनःसंरचना के लिए मामलों का चयन करने का विवेकाधिकार होता है। उपबंधित मानकों में छूट देने के इस युग में, फर्म के प्रबंधक का संबंध औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से बैंकरों के साथ रहता है जो इसीलिए उस ऋण पुनःसंरचना के लिए भी उनकी सहमति प्राप्त कर लेते हैं यद्यपि संभव न भी हो पाए तो भी। इस क्षमता ने पदधारी प्रबंधकों के प्रभाव को और शक्तिशाली बना दिया था। फर्म के बोर्ड के लिए ऐसे प्रबंधकों को उखाड़ फेंकना मुश्किल हो गया, भले ही वे अन्यथा अक्षम ही क्यों न हों। पदधारी प्रबंधन के बढ़ते प्रभाव के परिणामस्वरूप फर्मों का शासन कमजोर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकाल में हानिकारक परिणाम सामने आए।

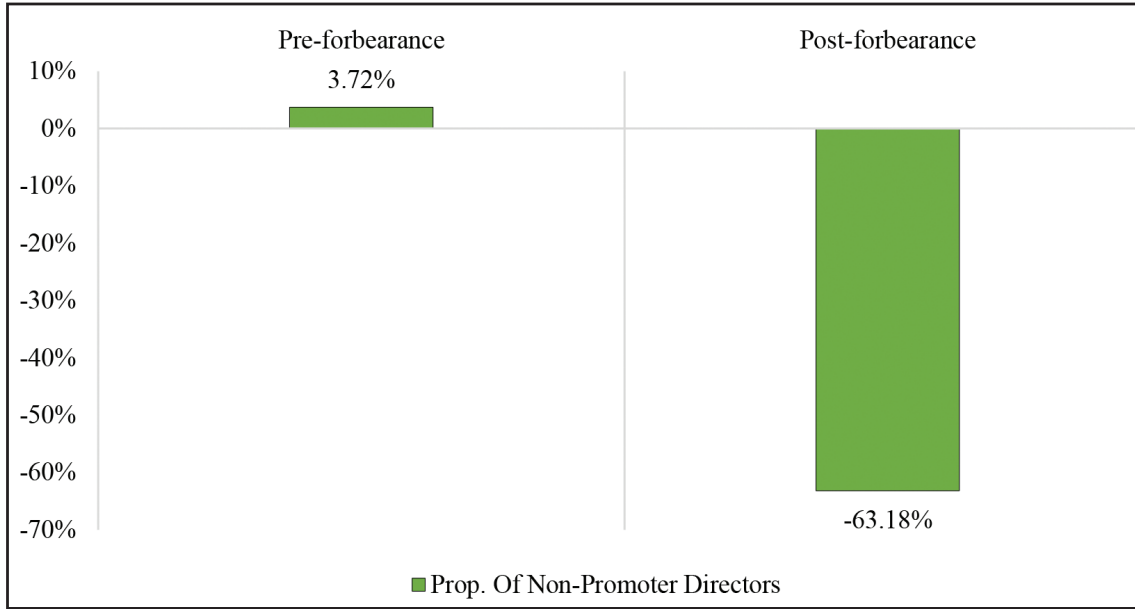
बोर्ड की गुणवत्ता में गिरावट

7.22 बोर्ड में, स्वतंत्र निदेशकों का होना, बोर्ड स्तर पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का एक मजबूत तंत्र है। यह मानें कि अधिकांश भारतीय फर्मों में संप्रवर्तक ही नियंत्रक शेयर धारक होते हैं, गैर-संप्रवर्तक निदेशकों की विशेष आवश्यकता इसलिए होती है जिससे छोटे शेयरधारकों के हितों की भी रक्षा की जा सके। ये फर्म प्रबंधक के स्रोतों के स्वत्वहरण अथवा मूल्य-ध्वंसक परियोजनाओं में निवेश जैसे अलाभकर कार्यों में आसक्त हो जाने की संभावना के विरुद्ध भी हितप्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, गैर-संप्रवर्तक निदेशकों के अनुपात में गिरावट का अर्थ है, फर्म में शासन का कमजोर होना।

7.23 फर्म के ऋण पुनः संरचना से 2 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पश्चात् के गैर-संप्रवर्तक निदेशकों के अनुपात में हुए परिवर्तन के प्रतिशत को चित्र-16 में दिखाया गया है। नियामक प्रविरति के प्रभाव की विशेषता पर बल देने के लिए चित्र में प्रविरत-अवधि (2009-2015) के दौरान फर्म की पुनः संरचना की तुलना प्रविरत-पूर्व-अवधि (2002-2006)² की पुनः संरचना के साथ की गई है। जैसा कि स्पष्ट है कि बोर्ड में गैर-संप्रवर्तक निदेशकों के प्रतिशत में महत्वपूर्ण ढंग से गिरावट पुनः संरचना के बाद प्रविरत-अवधि के दौरान हुई, जबकि इसके प्रतिशत में प्रविरत-अवधि से पूर्व की पुनः संरचना में हल्की सी वृद्धि हुई थी। इसलिए प्रविरत अवधि के दौरान बोर्ड में फर्म के सम्प्रवर्तकों ने प्रधानता प्राप्त कर ली। इसको बॉक्स-6 के जांच परिणामों द्वारा और अधिक प्रबलित किया गया। जैसा कि बताया गया है प्रविरति के परिणाम स्वरूप पदधारी प्रबंधकों के बढ़े हुए प्रभाव से प्राप्त हुआ क्योंकि (i) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति घट चुकी थी, (ii) सीईओ के अध्यक्ष बन जाने की प्रवणता बढ़ गई थी, (iii) बोर्ड में सम्बद्ध रूप से निर्णय करने वाले निवेशकों की संभावना बढ़ गई थी, (iv) बैंक द्वारा मॉनिटर किया जाना कम हो गया था क्योंकि बैंक द्वारा नामित निदेशकों को बोर्ड में स्थान नहीं दिया गया था।

²The pre-period is restricted until 2006 so that two years post-restructuring does not coincide with the Global Financial Crisis and the subsequent introduction of the forbearance

चित्र 16: कॉर्पोरेट शासन का कमजोर होना - बोर्ड में गैर-संप्रवर्तक निदेशक में कमी



स्रोत: पुनःसंरचना ऋणों के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय और बोर्डों के पुनर्गठन के लिए सी एम आई ई प्रोवेस

प्राविरिति पूर्व : वर्ष 2002-2006 के दौरान फर्म की पुनः संरचना के लिए 2 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पश्चात औसत परिवर्तन प्रतिशत

प्राविरिति पश्चात्: वर्ष 2009-2015 के दौरान फर्म की पुनः संरचना के लिए 2 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पश्चात् औसत परिवर्तन प्रतिशत

प्राविरिति द्वारा उपकृत उधारकर्ताओं द्वारा पूंजी का अक्षम आवंटन

7.24 ऐसा प्रतीत होता है कि खराब शासन के कारण उपकृत फर्म ने जो कि प्रवृत्त अवधि के अधीन थी अलाभप्रद परियोजनाओं में पूंजी का गलत आवंटन कर दिया था। जैसे कि चित्र 17 में दिखाया गया है प्रविरत-अवधि और इससे पूर्व की अवधि में पुनःसंरचित फर्म के पूंजीगत व्यय (केपेक्स) में केवल संतुलित वृद्धि ही दिखाई देती है। तथापि प्रविरत-अवधि में पुनः संरचित फर्मों की रुकी हुई संस्थापित परियोजनाओं की संख्या, अनुपात और रुपए मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। कुल रुकी हुई परियोजनाओं में (सभी केपेक्स परियोजना के अनुपात के रूप में) प्राविरिति के दौरान 40% (30%) की वृद्धि हुई थी, जबकि प्राविरिति पूर्व इनमें 12% (18%) की गिरावट आई थी। दूसरे शब्दों में प्रविरत-अवधि से पूर्व फर्मों द्वारा रुकी हुई परियोजनाओं को पुनः आरंभ करने की संभावना होती थी, जब पुनः संरचना के द्वारा ऋण का निवेश किया जाता था, जबकि प्राविरिति के अधीन फर्मों की अतिरिक्त परियोजनाओं रुक गई थीं जो यह सूचित करता है कि दिए गए ऋण का दुरुपयोग किया गया होगा।

बॉक्स 6: प्राविरिति से उपकृत फर्मों के लिए प्रबंधन की शक्ति में वृद्धि

डिफरेंस-इन-डिफरेंस तकनीक के उपयोग द्वारा जैसा कि बॉक्स-3 में चर्चा की गई है, इस बॉक्स में प्राविरिति और पदधारी प्रबंधकों की बढ़ती शक्ति के मध्य अनौपचारिक संबंध को पैनेल रिग्रेशन में दिखाया गया है जो कि सभी अस्तव्यस्त कारकों को नियंत्रित करता था। यहां फर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जिनका आकार, आयु, विशेष सुविधाएं और शोध-क्षमताएं समान हैं किंतु पुनः संरचना प्राप्त करने के लिए इनकी क्षमताएं भिन्न हैं। यह अंतर उनके बैंकों के साथ संभावित संबंधों के कारण उत्पन्न हुआ है। दो समूहों के लिए फर्म के परिणाम को इस प्रकार पुनः संरचना की संभावना में भिन्नता के गुण के रूप में देखा जा सकता है। चार परिणामों का अध्ययन किया गया - (i) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का अनुपात, (ii) सी ई ओ की द्वियात्मकता

अथवा फर्म के सीईओ का बोर्ड का अध्यक्ष भी होना, (iii) बोर्ड में समान संबद्धता का होना जिसका मापन जीवन-वृत्त (आयु, शिक्षा, निदेशनात्मकता आदि) के माध्यम से किया जा सकता है, (iv) बैंकों द्वारा नामित किए गए निदेशकों का निदेशक मंडल (बोर्ड) में अनुपात। कुछ चरों से संबंधित डाटा की उपलब्धता केवल प्रविरिति पश्चात् अवधि तक ही सीमित है। उस मामले में परिणामों की तुलना केवल उपचारित और नियंत्रित फर्मों के मध्य सिंगल डिफरेंस तक ही सीमित है। फर्म-वर्ष-स्तर का डाटा व्यवस्थित करने के उपरांत निम्नलिखित रिग्रेशन समीकरण का अनुमान लगाया गया है।

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \times Treatment_i \times Post_t + \beta_2 \times Treatment_i + \beta_3 \times X_{it} + \delta_i + \nu_t + \epsilon_{it}$$

इस समीकरण में फर्मों के अचल प्रभाव के साथ-साथ वर्षों को भी सम्मिलित किया गया है। यह अचल प्रभाव फर्मों में किसी भी अनदेखे विचलनों या वर्ष को अवशोषित कर सकते हैं जो कि अनुमानों को प्रभावित कर सकते हैं। परिणामों को नीचे दिखाया गया है-

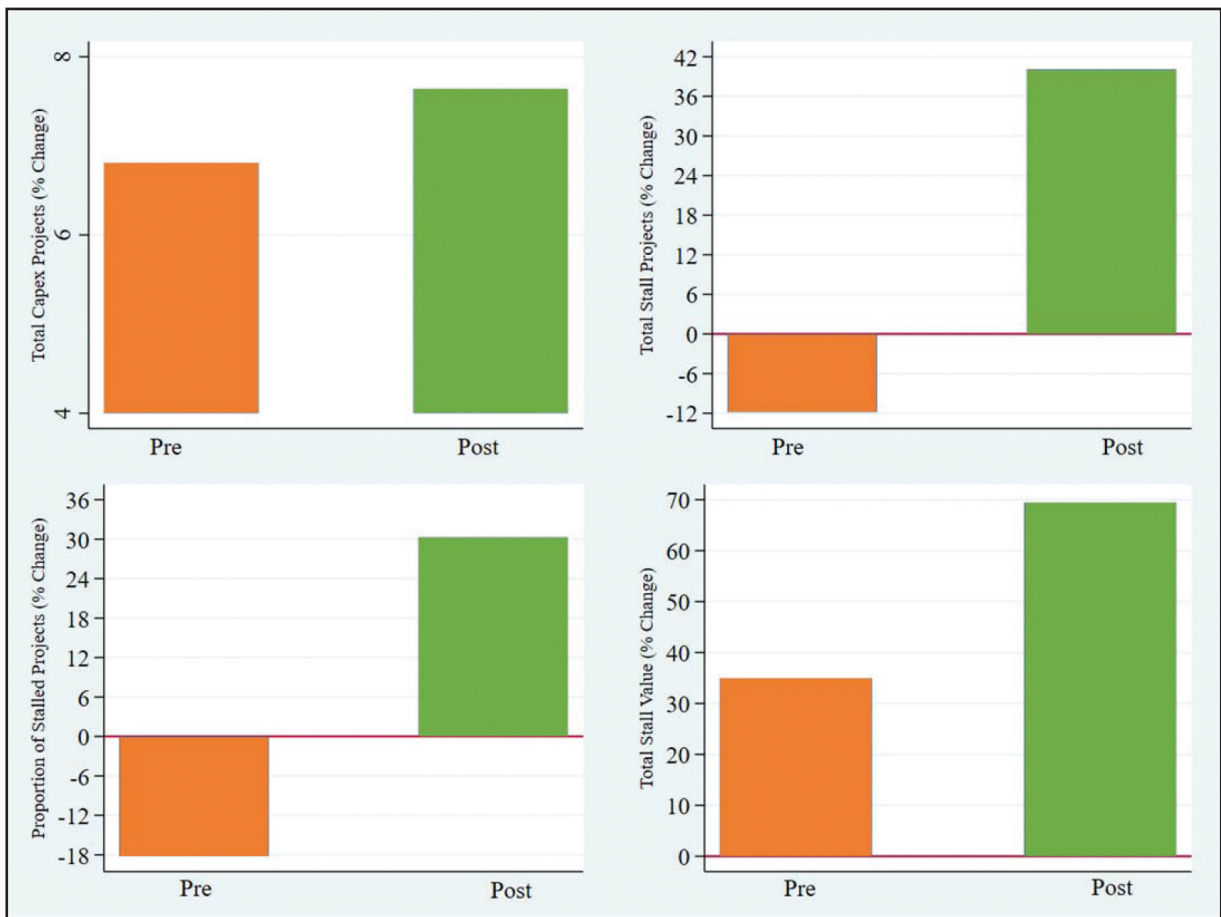
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VARIABLES	Independent Directors		CEO Duality		Similarity In Board		Banks' Nominee Directors	
Treatment X Post	-0.008**	-0.007**			0.012**	0.012*		
	(-2.587)	(-2.196)			(2.175)	(2.192)		
Treatment			0.02*	0.02*			-0.005**	-0.004**
			(1.715)	(1.70)			(-3.835)	(-3.053)
Controls	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes
Observations	83,844	82,862	7,826	7,796	10,323	10,285	7,827	7,797
R-squared	0.835	0.835	0.253	0.256	0.707	0.704	0.045	0.055
Fixed Effects	Firm and Year		Year		Firm and Year		Year	

तालिका-4: इस तालिका में डिफरेंस-इन-डिफरेंस अथवा सिंगल डिफरेंस गुण को फर्म के अंदर बोर्ड के गठन में परिवर्तन के अनुमान के लिए दिखाया गया है। वर्ष 2002 से 2015 तक के वर्षों के लिए फर्म-वर्ष स्तर पर आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के अनुपात को स्वतंत्र निदेशक द्वारा निरूपित किया गया है। सीईओ द्वायात्मकता एक सूचक चर होता है जिसका मान 1 होता है यदि सीईओ बोर्ड का अध्यक्ष भी बन जाता है अन्यथा इसका मान होता 0 होता है। इसी प्रकार बोर्ड के अंदर की संबद्धता को बोर्ड द्वारा निरूपित किया गया है जिसका आधार बोर्ड के सभी सदस्यों के जीवन वृत्त के मूल में कोसाइन सिमिलैरिटी का होना है। बैंक द्वारा नामित निदेशक, निदेशकों के उस अनुपात को निरूपित करते हैं जिनका नामांकन उधारदाता संस्थाओं द्वारा किया गया है। उपचार वह सूचक चर है जिसका मान फर्म के लिए 1 तब होता है जब फॉरबीयर्स से उच्च स्तर पर पुनर्गठन के रूप में माध्यिका से ऊपर लाभ प्राप्त होता है। पोस्ट एक अन्य सूचक चर है जिसका मान वर्ष 2009 से 2015 के लिए 1 लिया गया है अन्यथा इसका मान शून्य है। जिसको समसंख्यांकित कॉलम में सम्मिलित किया गया है जो कि फर्म स्तर के समय परिवर्तनीय नियंत्रण चर को निरूपित करता है: बैंकिंग संबंधों की संख्या, औसत ऋण अवधि, पिछले 5 वर्ष में चुकाए गए ऋण। फर्म के स्थाई प्रभाव द्वारा दिखाया गया है जबकि वार्षिक स्थाई प्रभाव को दिखाता है। स्टैंडर्ड एरर (मानक त्रुटि) जिनको कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है * P < 0.1; ** p < .05; *** p < 0.01A

स्रोत: चोपड़ा, निशेश, और तंत्री (2020)।

सभी चरों के गुणांक से मानक स्तर पर सांख्यिकीय महत्व निकलता है। स्वतंत्र निदेशकों और बैंक के नामित निदेशकों के लिए गुणांक ऋणात्मक हैं तथा सीईओ द्वयात्मकता तथा बोर्ड में समानता के लिए घनात्मक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि फर्मों में बोर्ड की गुणवत्ता फॉरबीयरेंस से उपकृत होने के स्थान पर और अधिक कमजोर हो जाती है क्योंकि उनके स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में गिरावट आ जाती है। यहां तक कि बैंक के नामित निदेशकों का प्रतिनिधित्व कम होने की वजह से उधारदाता संस्थानों द्वारा मॉनीटरिंग भी कम हो जाता है और साथ ही ऐसी फर्मों में पदधारी प्रबंधक और शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसी फर्मों का बोर्ड उनके प्रबंधन से संबंधित नए सदस्यों को रखने की संभावना बना देता है और फर्म के सीईओ के बोर्ड का अध्यक्ष बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। सारांश के रूप में इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि फॉरबीयरेंस से बोर्ड पर पदधारी प्रबंधक के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है।

चित्र 17: फॉरबीयरेंस के दौरान ऋण का दुरुप्रयोग-पुनः संरचना से उपकृत फर्मों के साक्ष्य



स्रोत: (पुनः संरचना ऋणों के लिए)-कारपोरेट कार्य मंत्रालय

बोर्डों के पुनर्गठन के लिए-सीएमआईई कौशल

फॉरबीयरेंस पूर्व: वर्ष 2002-2006 के दौरान फर्म की पुनः संरचना के लिए 2 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पश्चात औसत परिवर्तन प्रतिशत

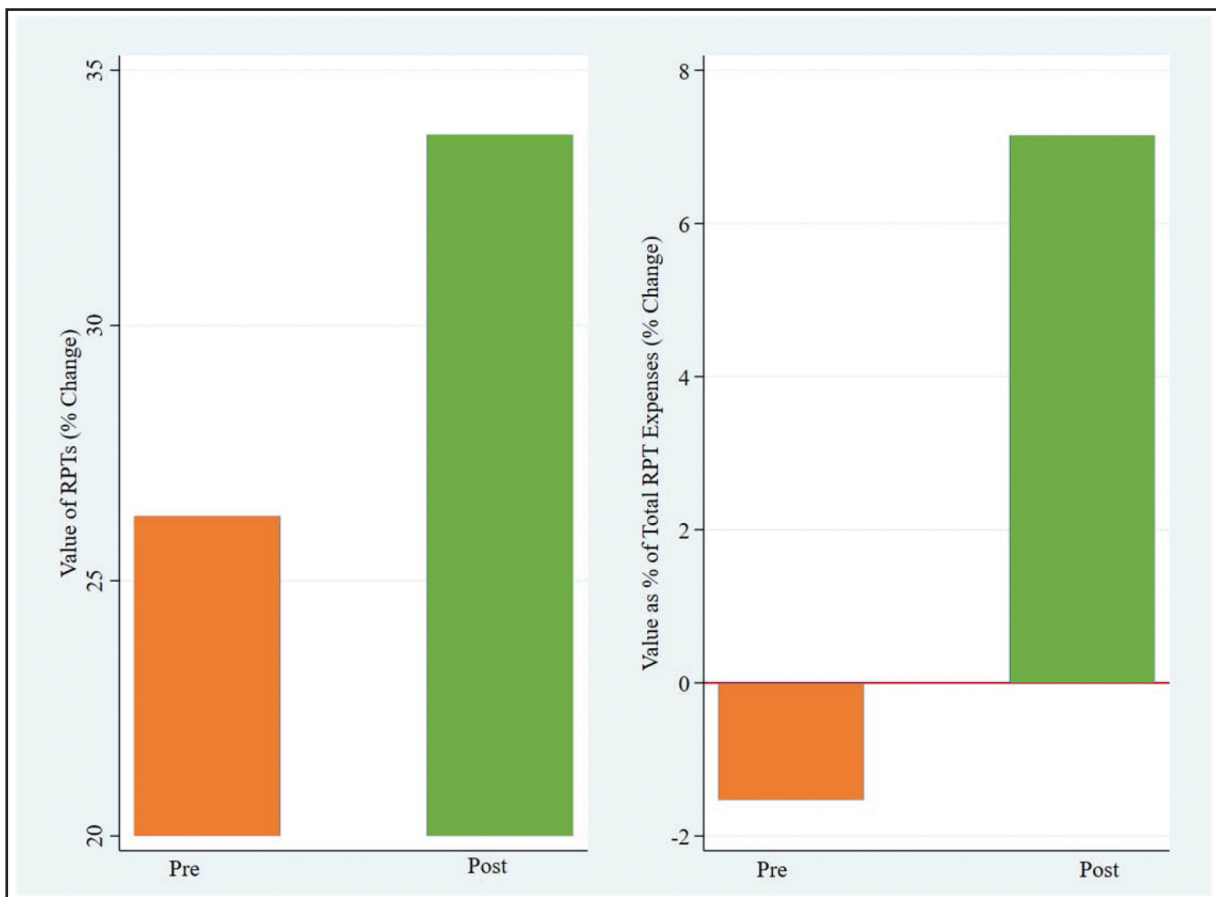
फॉरबीयरेंस पश्चात: वर्ष 2009-2015 के दौरान फर्म की पुनः संरचना के लिए वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पश्चात औसत परिवर्तन प्रतिशत

फॉरबीयरेंस से उपकृत उधारकर्ता द्वारा स्रोतों का दुर्विनियोजन

7.25 घटते शासन और शक्तिशाली प्रबंधक-वर्ग के प्रभाव का एक अतिरिक्त संभावित परिणाम था कि निजी लाभ फर्मों के प्रबंधक भेजे जाने लगे थे। भारतीय संदर्भ में संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) का उपयोग

फर्म के संसाधनों के स्वत्वहरण को छद्मावरण पहनाने के लिए किया जाता है। पदधारी प्रबंधक फर्म को ऐसे संबंधित पार्टी लेने में व्यस्त करने के लिए बाध्य कर सकते हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधक वर्ग से संबंधित तत्व सम्मिलित होते हैं। इसे चित्र 18 में दिखाया गया है। उन फर्मों के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के संबंधित पार्टी लेने-देने में लगभग 34% की वृद्धि पाई जाती है। इसकी तुलना में फॉरबीयरेंस से पूर्व फर्मों की पुनः संरचना महत्वपूर्ण कर्मचारियों के संबंधित पार्टी लेने-देने को देखा जाता है तो इसमें 7% की वृद्धि पाई जाती है। इसकी तुलना में फॉरबीयरेंस से पूर्व फर्मों की पुनः संरचना महत्वपूर्ण कर्मचारियों के संबंधित पार्टी लेने-देने में 26% की वृद्धि दिखाती है किंतु कुल व्यय के अनुपात में इसमें 1.5% की गिरावट आती है। बॉक्स-7 में सावधानी से किए गए पैनेल रिग्रेशन के परिणाम को दिखाया गया है जो दर्शाता है कि फॉरबीयरेंस-अवधि में समग्र प्रबंधक क्षतिपूर्ति और निदेशक की सिटिंग फीस (बैठक शुल्क) में उठाल आया है। इसलिए बढ़ी हुई और ढीली-ढाली पुनः संरचना का परिणाम यह हुआ कि फर्म के स्रोतों का दुर्विनियोजन अल्पसंख्यक शेयरहोल्डरों की कीमत पर हुआ।

चित्र 18: फर्म के संसाधनों का दुर्विनियोजन-महत्वपूर्ण कर्मचारियों के संबंधित पार्टी लेने-देने से साक्ष्य



स्रोत: पुनर्गठित ऋणों के लिए-कारपोरेट कार्य मंत्रालय और बोर्डों के पुनर्गठन के लिए-सीएमआईई प्रोवेस

फॉरबीयरेंस पूर्व: वर्ष 2002-2006 के दौरान पुनर्गठित फर्म के लिए 2 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पश्चात औसत परिवर्तन प्रतिशत

फॉरबीयरेंस पश्चात्: वर्ष 2009-2015 के दौरान पुनर्गठित फर्म के लिए दो वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पश्चात औसत परिवर्तन प्रतिशत

फॉरबीयरेंस से उपकृत उधारकर्ताओं के कार्य निष्पादन में गिरावट

7.26 कमज़ोर शासन के परिणामस्वरूप प्रभावित फर्म के कार्य निष्पादन में गिरावट आ गई। चित्र-19 में फर्म के महत्वपूर्ण मूल अनुपातों में उद्योग समायोजित परिवर्तन को दर्शाया गया है, पुनर्गठन से 2 वर्ष पूर्व और 2

वर्ष पश्चात् और इसे फॉरबीयर्स-अवधि पूर्व और पश्चात् के संगत दिखाया गया है। फॉरबीयर्स-अवधि में पुनर्गठन फर्म के ऋण और इक्विटी के ऋण के अनुपात के रूप में आंके गए लाभ में महत्वपूर्ण 15.7% वृद्धि हुई थी और इसके साथ ही फॉरबीयर्स अवधि के दौरान फर्म के पुनर्गठन के लिए इंटेरेस्ट कवरेज में भी 27.2% गिरावट आई। जैसा कि पहले बताया गया है ब्याज-सुरक्षा फर्म की उस क्षमता का मापन करती है जिससे वर्तमान लाभों से ऋण के ब्याज भरने का व्यय सुरक्षित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फॉरबीयर्स से पूर्व फर्म का पुनर्गठन हो जाता है और विशेष सुविधाओं में 3.4% की कमी हो जाती है और उनके ऋण के पुनर्गठन के उपरांत ब्याज-सुरक्षा में 49.6% की वृद्धि हो जाती है। फर्म की लिक्विडिटी पर भी हानिकारक प्रभाव प्रतीत होता दिखाई देता है जिसका पता फर्म के त्वरित-अनुपात³ (क्विक-रेश्यो) में 30% की गिरावट से चलता है, जिसमें पूर्व-अवधि में केवल 4% की उपांतिक गिरावट हुई थी³। अंततः फर्म की लाभप्रदता में, जिसका मापन फर्म की परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है फॉरबीयर्स-अवधि में 138% से अधिक की तेज गिरावट आई थी। दूसरे शब्दों में, फॉरबीयर्स-अवधि के दौरान पुनर्गठन से उपकृत फर्म, औसतन देखा जाए, तो हानि में जा रही थी, जबकि पूर्व फॉरबीयर्स-अवधि में पुनर्गठन फर्मों की लाभप्रदता में लगभग 15% का सुधार हुआ था। समग्रतः जहां पूर्व फॉरबीयर्स काल में पुनर्गठन द्वारा फर्म के मूल में सुधार हो रहा था वहीं फॉरबीयर्स के दौरान यहां उनमें उल्लेखनीय गिरावट आ गई। नोट करें कि इन मानों का समायोजन उद्योग और वर्ष के लिए किया जाता है और ये इस प्रकार फॉरबीयर्स-अवधि के दौरान समष्टि अर्थशास्त्र (मैक्रोइकनॉमिक्स) के आघात द्वारा प्रभावित नहीं हुए हैं।

बॉक्स 7: फॉरबीयर्स से उपकृत फर्मों द्वारा संसाधनों का दुर्विनियोजन

बॉक्स-6: में बताई गई डिफरेंस-इन-डिफरेंस विधि के उपयोग द्वारा इस बॉक्स में फॉरबीयर्स से उपकृत फर्मों के बोर्ड पर वर्धित पारिश्रमिक पर फॉरबीयर्स के प्रभाव को दिखाया गया है। इससे दो परिणाम सामने आए हैं (i) प्रबंधक वर्ग की क्षतिपूर्ति और आरपीटी-फर्म में महत्वपूर्ण पदों को की गई कुल क्षतिपूर्ति जिसमें उनके साथ किया गया किसी भी प्रकार का संबंधित पार्टी लेनदेन सम्मिलित है और (ii) निदेशक का वेतन-जिसमें बोर्ड के सभी निदेशकों का कुल पारिश्रमिक आता है। अभिनिर्धारण और रिग्रेशन फ्रेमवर्क को समान रखते हुए निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं:

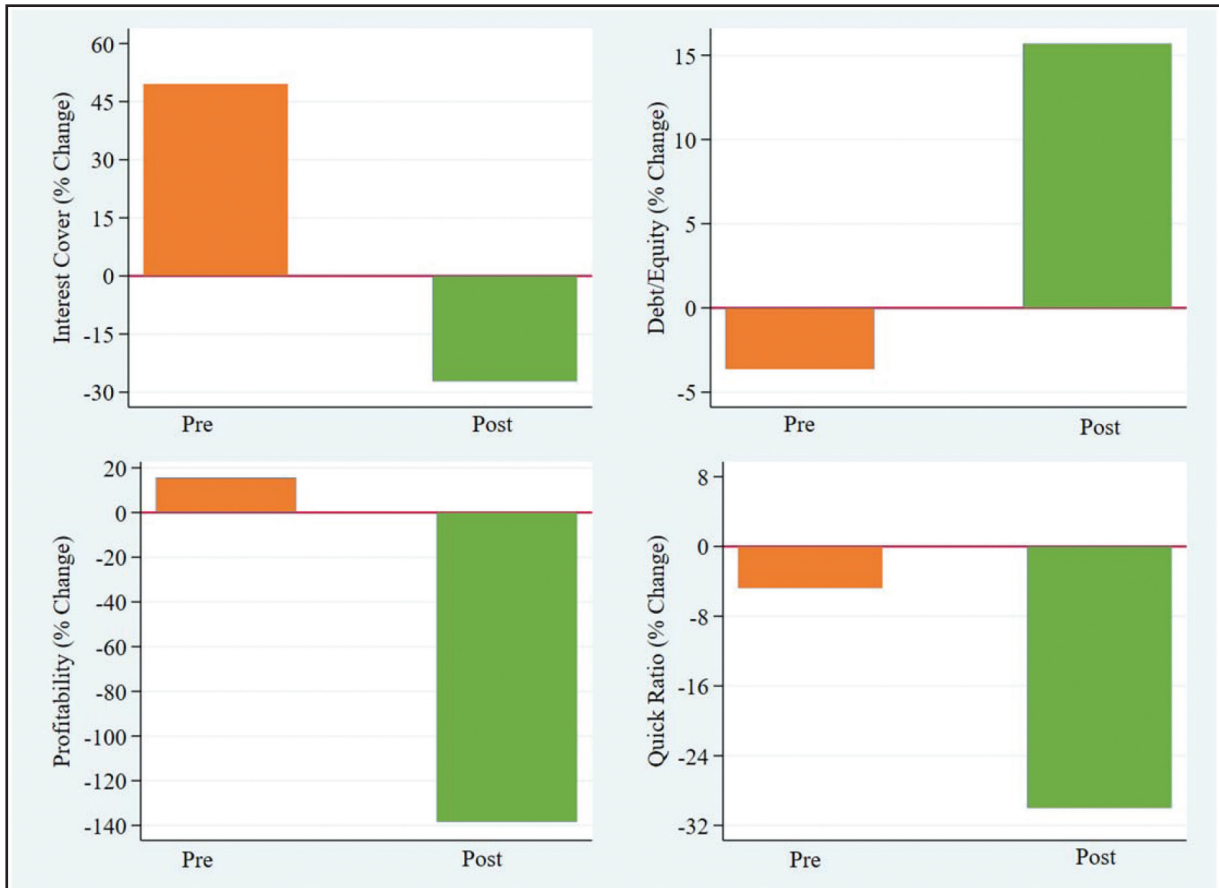
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Management Compensation and RPT		Directors Salary	
Treatment X Post	0.231**	0.242***	0.071*	0.075*
	(2.492)	(2.619)	(1.788)	(1.916)
Controls	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
Observations	91,566	90,576	38,931	38,579
R-squared	0.688	0.689	0.817	0.818
एफई	प्रतिष्ठान और वर्ष			
क्लस्टरिंग	प्रतिष्ठान			
Observation Level	प्रतिष्ठान-वर्ष			

तालिका 5: तालिका प्रतिष्ठानों के भीतर प्रबंधन की क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाने के लिए डिफरेंस-इन-डिफरेंस का विशेष विवरण दर्शा रही है। परिणाम चर ऊपर बताए गए हैं। तालिका 4 में सभी चर और नोटेशन समान हैं।
स्रोत: चोपड़ा, निशेष और तंत्री (2020)।

³ एक फर्म के लिए, त्वरित अनुपात को उसकी वर्तमान देनदारियों और वर्तमान संपत्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

दोनों चरों के लिए गुणांक सकारात्मक हैं और मानक सांख्यिकीय महत्व है। फॉरबीयरेंस प्रतिष्ठानों को लाभ होने की संभावना है, इससे उनके प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि फॉरबीयरेंस से प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को लाभ वृद्धि पुनः प्रेषित होती है।

चित्र 19: ऑपरेटिंग मेट्रिक्स में गिरावट और फॉरबीयरेंस से लाभान्वित होने वाले प्रतिष्ठानों का निष्पादन



स्रोत: एमसीए (पुनर्गठित ऋण हेतु) और सीएमआईई कौशल, बोर्ड गठन के लिए

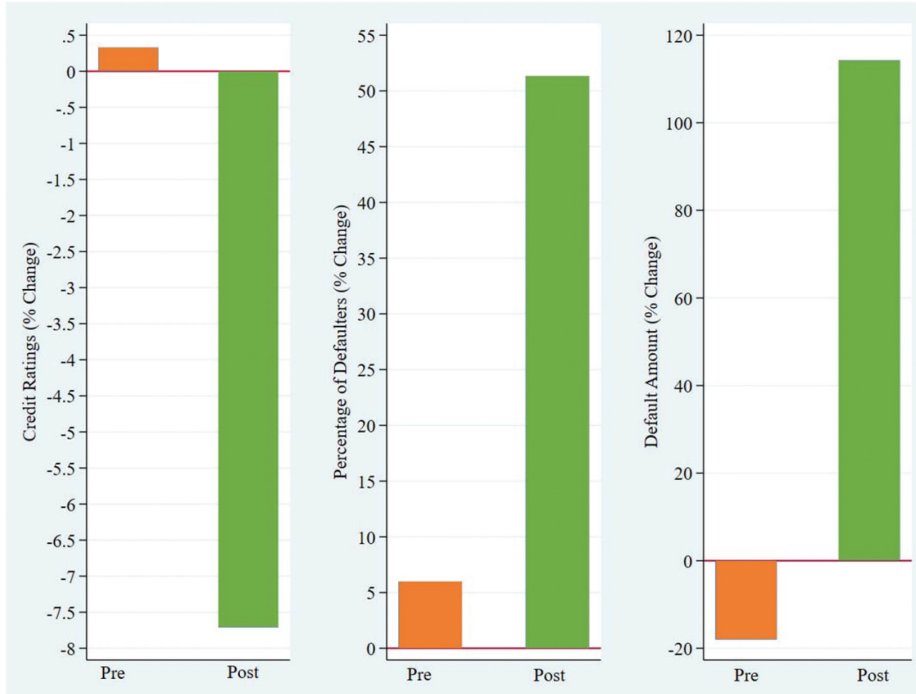
प्री: 2002-2006 के दौरान प्रतिष्ठान पुनर्गठन के दो वर्ष बाद और पूर्व औसत प्रतिशत परिवर्तन

पोस्ट: 2009-2015 के दौरान प्रतिष्ठान पुनर्गठन के दो वर्ष बाद और पूर्व औसत प्रतिशत परिवर्तन

फॉरबीयरेंस से लाभार्थी उधारकर्ताओं द्वारा बढ़ते डिफाल्ट

7.27 उनके मूल सिद्धांतों में क्षय के परिणामस्वरूप फॉरबीयरेंस विकल्प में पुनर्गठित प्रतिष्ठानों की क्रेडिट रेटिंग में भी कमी देखी गई है। चित्र 20 दर्शाता है कि एक प्रतिष्ठान की औसत क्रेडिट रेटिंग फॉरबीयरेंस व्यवस्था के दौरान पुनर्गठन पर 7.7% कम हो गई, जबकि फॉरबीयरेंस पूर्व इसमें मामूली सुधार (0.33%) था। फॉरबीयरेंस व्यवस्था में पुनर्गठित प्रतिष्ठानों ने अधिक डिफाल्ट्स किये जो फॉरबीयरेंस पूर्व व्यवस्था की तुलना में कम थे। फॉरबीयरेंस अवधि में पुनर्गठित प्रतिष्ठानों के अनुपात जो चूककर्ता में 51% की वृद्धि हुई, जबकि पूर्व-अवधि में यह वृद्धि तुलनात्मक रूप से मामूली थी (6% द्वारा)। डिफाल्ट के अंतर्गत राशि के संदर्भ में, फॉरबीयरेंस पूर्व के मूल्य में 18% की कमी की तुलना में फॉरबीयरेंस बाद में यह आंकड़े दोगुना से अधिक (114% की वृद्धि) है। एक बार फिर, फॉरबीयरेंस पूर्व अवधि में पुनर्गठन से लगता है कि संकटग्रस्त और चूक करने वाले कर्जदारों को अपने कर्ज को चुकाने और अपने डिफाल्टर टैग को हटाने में सहायता मिली है। हालांकि, फॉरबीयरेंस विकल्प के दौरान पुनर्गठन से लाभान्वित प्रतिष्ठानों ने औसतन अधिक चूक करना शुरू किया है।

चित्र 20: फॉरबीयरेंस के कारण त्वरित फर्म डिफाल्ट

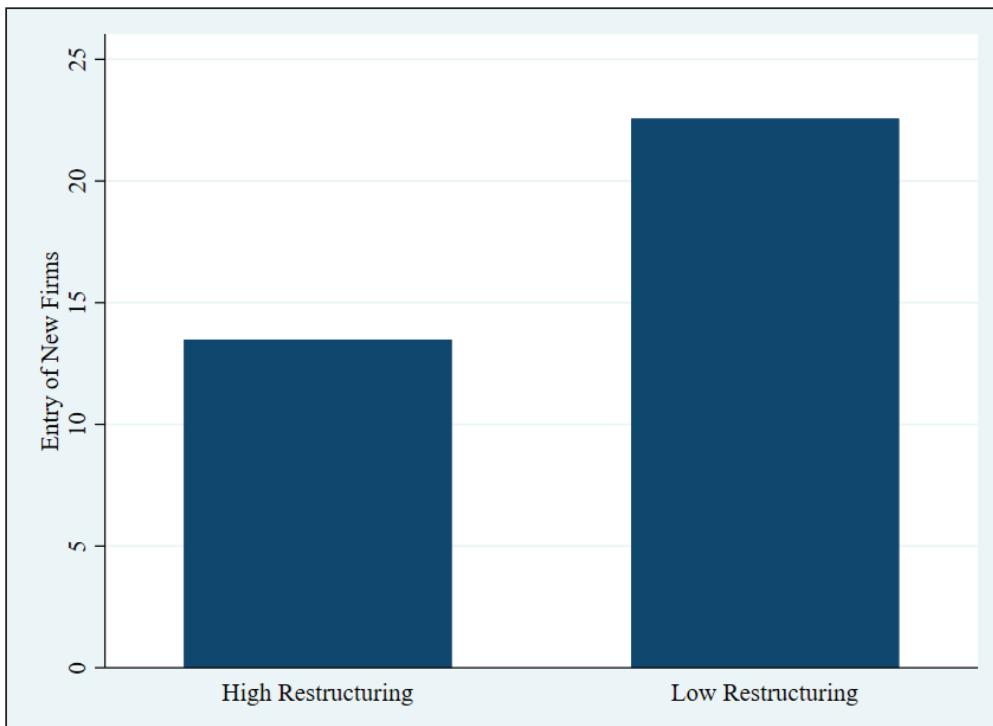


स्रोत: एम सी ए (पुनर्गठित ऋण हेतु) क्रेडिट रेटिंग के लिए सी एम आई ई प्रॉसेस तथा डिफाल्टर्स के दायर मुकदमों के डेटाबेस के लिए जी आई बी आई एल वेबसाइट।

पूर्व: 2002-2006 के दौरान फर्मों के पुनर्गठन के दो वर्ष बाद और पूर्व औसत प्रतिशत परिवर्तन

पश्च: 2009-2015 औसत के दौरान फर्मों के पुनर्गठन के दो वर्ष बाद और पूर्व औसत प्रतिशत परिवर्तन

चित्र 21: समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रभाव फॉरबीयरेंस के कारण बढ़े प्रतिष्ठान डिफाल्ट्स



7.28 निष्कर्षतः संकटग्रस्त उधारकर्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु बनी दीर्घकालीन छूट नीति भविष्य में प्रतिष्ठानों के लिए अनायास ही नकारात्मक परिणाम लाएगी। प्रतिष्ठानों का आंतरिक शासन कमजोर हुआ है, संसाधनों का दुर्विनियोजन बढ़ा है और उनके मूल सिद्धांतों का ह्रास हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र के मोर्चे पर, जैसा कि चित्र 21 में दर्शाया गया है, के विकल्प के तहत, उद्योग के भीतर पुनर्गठित प्रतिष्ठानों का एक बड़ा हिस्सा भी उद्योग में नए प्रतिष्ठानों के प्रवेश में कमी से जुड़ा हुआ है।

पर्याप्त पूंजीकरण के बिना बैंक क्लीन अप

7.29 अंततः, लगातार सात साल से फॉरबीयरेंस के बाद, आरबीआई ने अप्रैल 2015 से प्रारंभ हुई विनियामक फॉरबीयरेंस को मजबूरन वापस लेने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने बैंकों के एनपीए की सही स्थिति को जानने के लिए विस्तृत परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) थी। तथापि, चोपड़ा सुब्रमण्यम और तंत्री (2020) प्रलेख के रूप में, एक्यूआर ने इस समस्या को और बढ़ा दिया क्योंकि यह न तो बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने को अनिवार्य बनाता है और न ही पूंजीगत बैकस्टॉप प्रदान करता है, हालांकि यह निश्चित था कि बैंकों की एक्यूआर अनुसरण के बाद प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

7.30 आर्थिक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि इस तरह के एक्यूआर के साथ दो प्रतिकूल परिणाम संभव थे। आशावादी दृष्टिकोण में, यह अपेक्षित था कि एक्यूआर से सूचना विषमता में कमी होगी। डायमंड और राजन, 2011 में परिकल्पित एक महत्वपूर्ण धारणा के अनुसार, रिज़ल्टेंट क्लीनर बैंक बैलेंस शीट, बैंकों को अपने बल पर अधिक निजी पूंजी जुटाने में मदद करेगी, जिससे वित्तीय मध्यस्थता की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस दिशा में आरबीआई का दृष्टिकोण यह था कि योजना एक तरह की “गहन सर्जरी” थी जिससे स्वस्थ बैंक बैलेंस शीट बने (राजन, 2016)।

7.31 हालांकि, पूंजी जुटाने की संभावना पर विषम सूचना समस्या के प्रभाव के उपयोग से एक उत्तम परिणाम की अपेक्षा की जा सकती थी। मायर्स एण्ड मजलुफ (1984) का अनुमान है कि घाटाग्रस्त प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों के रूप में स्वेच्छा से इक्विटी बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा, प्रबंधक, निवेशकों की तुलना में प्रतिष्ठानों के मूल सिद्धांतों को अधिक जानते हैं जिससे इक्विटी के मूल्य के कमजोर पड़ने का डर है। अतः, अनिवार्य पूंजी जुटाने या पूंजी बैकस्टॉप के लिए एक नीति की अनुपस्थिति के कारण सब शेरधारकों और बैंक प्रबंधकों पर आश्रित है, जो नियामकों और निवेशकों की तुलना में बैंक के मूल सिद्धांतों के बारे में अधिक जानते हैं, नियामकों और निवेशकों के पास इक्विटी पूंजी जुटाने को कोई प्रोत्साहन नहीं है। अप्रत्यक्ष सरकारी गारंटी से पूंजी जुटाना हतोत्साहित होता है (अदमाती और हैलवीग, 2014)। नतीजतन, कम-पूंजीकृत बैंक फिर से जोखिम-स्थानांतरण और जौबी लैंडिंग का सहारा ले सकते हैं, जिससे समस्या और गंभीर रूप से ले सकती है। प्रतिकूल प्रभाव वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए, सही उधारकर्ताओं और परियोजनाओं को क्रेडिट से वंचित रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था की निवेश दर में परिणामी गिरावट, आर्थिक विकास को बढ़ा सकती है। चोपड़ा, सुब्रमण्यम और तंत्री (2020), ने सचेत करने वाले सबूत दिये हैं कि यह यकीनन एक्यूआर अनुसरण से हुआ है।

बाकी दुनिया में बैंक क्लीन-अप्स के सामने महत्वपूर्ण अंतर

7.32 इस संदर्भ में, यह जानना महत्वपूर्ण है कि जापान, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसी मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में किए गए विशिष्ट बैंक क्लीन-अप्स से भारतीय एक्यूआर दो प्रमुख पहलुओं में भिन्न है। सबसे पहले, क्लीन-अप तब किए गए जब देश आर्थिक संकट से नहीं गुजर रहा था। जैसा खंड 8.30 में बताया गया है, आरबीआई ने आर्थिक स्थिरता को देखते हुए, माना कि बैंक बही साफ-सुथरी होने पर बाजार, बैंकों को आवश्यक पूंजी की आपूर्ति करेंगे। दूसरा, न तो बैंकों को पुनः पूंजीकरण के लिए

बाध्य किया गया था और न ही इसके लिए कोई स्पष्ट आरबीआई ने इस अनुमान के साथ एक्यूआर की शुरुआत की कि क्लीन-अप के कारण अतिरिक्त ऋण प्रावधान की आवश्यकता के विस्तार से बैंकों में अत्याधिक पुनः पूंजीकरण की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी। किसी भी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में एक्यूआर प्रयोग के बारे में स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, हम एक्यूआर में शामिल धारणाओं को समझने के लिए आरबीआई के तात्कालीन गवर्नर के भाषणों पर भरोसा करते हैं।⁴

उदाहरण के लिए, राजन (2016) में कहा: “सरकार पूर्ण रूप से शामिल है और समर्थन कर रही है। हमने संभावित परिणामों पर बहुत से परिदृश्यों को आरेखित किया है।⁴ वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आवश्यकतानुसार पूंजीगत सहायता प्रदान करेंगे। हमारा अनुमान है कि सरकार ने जो समर्थन इंगित किया है वह पर्याप्त होगा..... हमारा अनुमान है कि किसी भी पुनः पूंजीकरण के आभाव में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एक छोटी संख्या द्वारा न्यूनतम प्रमुख पूंजीगत आवश्यकताओं का कोई भी उल्लंघन, छोटा होगा..... सरकार पहले ही स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है, हमारी दृष्टि में, सभी उचित परिदृश्यों की संभालने में सक्षम है, सरकार आवश्यकतानुसार अपने बैंकों के समर्थन में खड़ी है।” आरबीआई ने योजना की अस्थायी परिकल्पना कि है और बैंकिंग सेक्टर की “मार्च 2017 तक बैलेंस शीट को साफ और पूरी तरह से प्रावधानित बताया है..... संक्षेप में, जबकि कुछ बैंकों की लाभप्रदता अल्पकालिक रूप से प्रभावित होगी, सिस्टम, एक बार साफ हो जाने पर, एक सतत और लाभदायक आर्थिक विकास का समर्थन करने में सक्षम होगा।” निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए, आरबीआई ने आशा व्यक्त की है कि “हमारे परिदृश्य यह भी दर्शाते हैं कि निजी क्षेत्र के बैंक इस प्रयास के परिणामस्वरूप नियामक पूंजी नहीं चाहेंगे।”

बैंक बैलेंस शीट का अपर्याप्त क्लीन-अप

7.33 वास्तविकता में, एक्यूआर उपयोग ने एनपीए के साथ-साथ परिणामित पूंजीगत संचार के पूर्व प्रभाव का अनुमान बहुत कम लगाया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि बैंक बैलेंस शीटें दुरुस्त बनें। अतिरिक्त (सकल) एनपीए के संदर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2016 के वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2019⁵ अंत तक 5.65 लाख करोड़ रुपए जोड़े। इस राशि को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, अतिरिक्त एनपीए ने इस अवधि में कुल का राजस्व कर लगभग 7.9 प्रतिशत योगदान दिया।

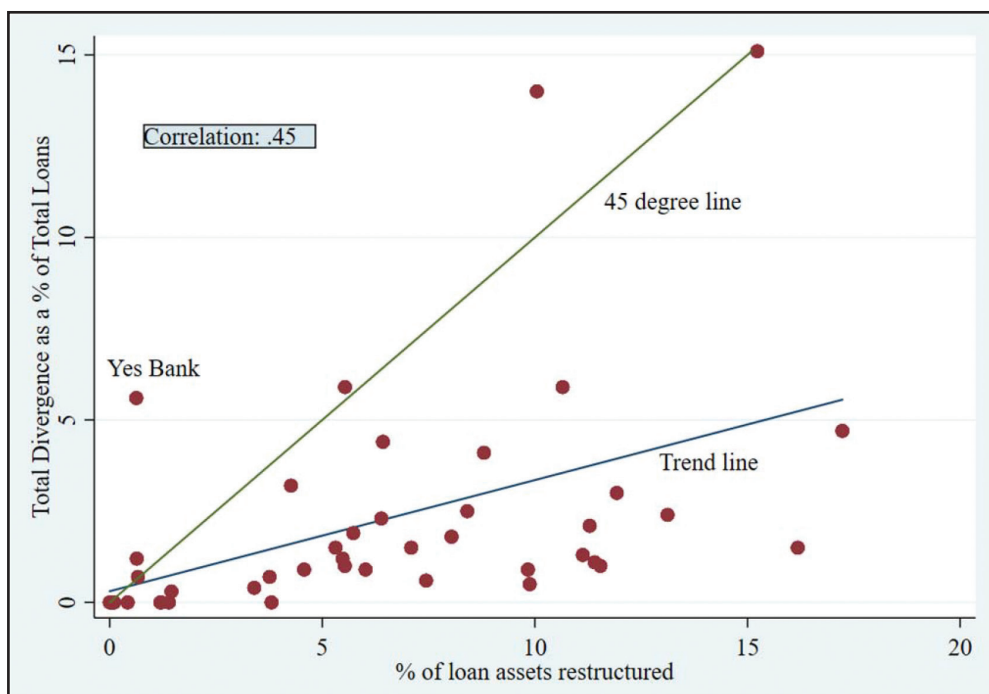
7.34 वस्तुतः एक्यूआर ने बैंक बैलेंस शीट में व्याप्त विषमताओं को कम किया है। एक्यूआर व्यवस्था (वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2019) के दौरान अपने एनपीए विचलन के विरुद्ध बैंकों (वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2015) द्वारा पुनर्गठित ऋणों के संचित अनुपात को चित्र 22 में आलेखित किया गया है। कुल ऋणों के अनुपात में, बैंक द्वारा प्रतिवेदित एनपीए नम्बरों और आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के बीच का अंतर, एनपीए विचलन होता है। एक सकारात्मक सहसंबंध इंगित करता है कि एक्यूआर ने पुनर्गठित कार्यकलापों द्वारा उधार दिए गए कुछ खराब ऋणों की पहचान की है। हालांकि, एक्यूआर उपयोग की प्रभावशीलता का अनुमान इस तरह के एक सरल सकारात्मक सहसंबंध द्वारा नहीं लगाया जा सकता, विशेषकर दिए गए सांख्यिकीय रूप से कम सहसंबंध (0.45) द्वारा। इसके

⁵ एक्यूआर का एकमात्र उल्लेख जून 2016 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि “सकल गैर-निष्पादित अग्रिम (जीएनपीएएस) अनुपात, सितंबर 2015 और मार्च 2016 के बीच 5.1 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गया है, जो संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के कारण गैर-निष्पादित के रूप में मानक अग्रिम के पुनर्गठन के वर्गीकरण को दर्शाता है।” स्पष्टतः, इस प्रयोग में अनुसरण की गई प्रक्रिया या शामिल पूर्वधारणाओं के बारे में रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं है।

अलावा, ध्यान दिया जाए कि ज्यादातर बैंक 45° रेखा से नीचे पाए गए हैं। इसका अर्थ है कि, ज्यादातर मामलों में, बैंक द्वारा पुनर्गठित ऋणों की तुलना में पहचाने गए एनपीए आकार में छोटे थे।

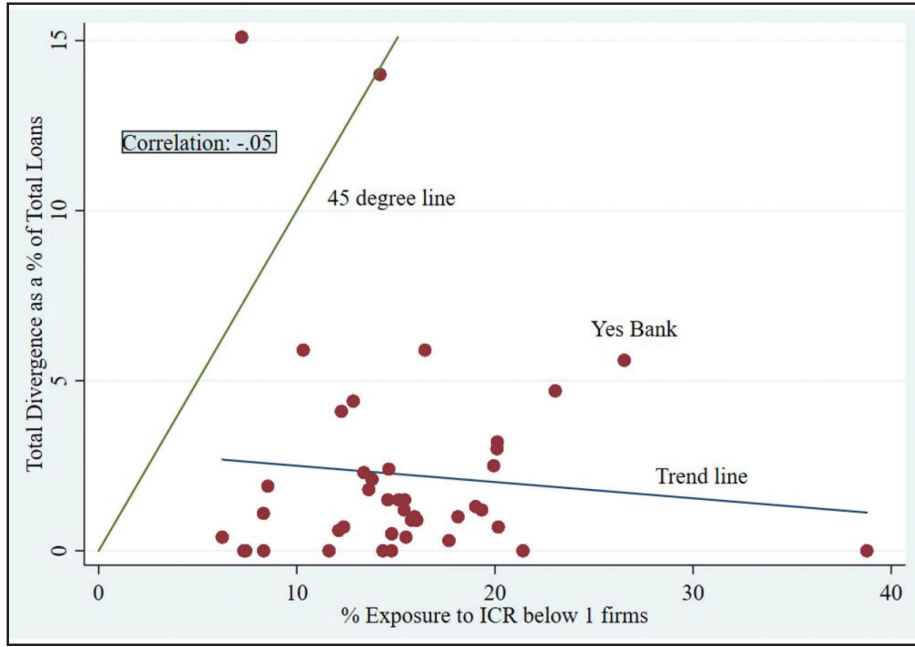
7.35 कश्यप, महापात्रो और तांत्री (2020) का तर्क है कि एक्यूआर जटिल अक्षय कार्यकलापों की पहचान करने के बजाय, पुनर्गठन द्वारा खराब उधार को लक्षित करने तक सीमित था। ध्यान दे कि ऋण पुनर्गठन खुलासे का समर्थन करता है जबकि नए ऋण प्रदान नहीं करता। अतः पुनर्गठन की बजाय बैंक डिफॉल्ट की कगार पर मौजूदा उधारकर्ता को आसानी से एक नया ऋण दे सकते थे। अपने प्रलोभनों को और अधिक छिपाने के लिए, बैंक, वास्तविक संकटग्रस्त प्रतिष्ठान के संबंधित पक्षों के नेटवर्क को नए ऋण के रूप में छिपे हुए भुगतान कर सकते हैं। चित्र 23 और 24 में, बैंकों द्वारा बताए गए सकल एनपीए विचलन के विरुद्ध इन दो जटिल अक्षय संभावनाओं के रूप में उधार दिए। (वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2015) जिसे संचित अनुपात बताया गया है। चित्र 23 में एक से कम ब्याज व्याप्ति के साथ उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष ऋण के अनुपात को दर्शाया गया है, जबकि चित्र 24 में संबंधित पक्षों के चैनल द्वारा इस प्रकार के उधारकर्ताओं के ऋण संबंधित कार्यकलापों को बताया गया है। विचलन और अक्षय उपायों के बीच अत्यधिक कम सहसंबंध (जो वास्तव में, एक मामले में मामूली रूप से नकारात्मक है) दर्शाता है कि एक्यूआर प्रयोग विचलन अक्षय को पहचानने में विफल हुआ और इस प्रकार विकृत ऋणों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा हो। बैंकों के आंकड़ों में लगभग सभी बैंक 45° रेखा के नीचे आते हैं जो आगे इंगित करते हैं कि प्रयोग के दौरान अक्षय संभावनाओं के बहुत मामूली विस्तार पाए गए हैं। दिलचस्प है कि, यस बैंक, जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा बचाया गया था, इन दोनों ग्राफों में अलग से खड़ा है। जहां बैंक का विचलन केवल 5% के आसपास था, जबकि इसका अक्षय सूचक 38%-52% के बीच अधिकतम था। बैंकों द्वारा प्रतिवेदित एनपीए (वित्तीय वर्ष 2016 में 0.75% से वित्तीय वर्ष 2020 में 16.8%) में तेज वृद्धि, इस विश्लेषण के आधार पर अप्रत्याशित नहीं लगती।

चित्र 22: एक्यूआर द्वारा क्लीन अप-पुनर्गठित कार्यकलापों के साथ सकारात्मक सहसंबंध



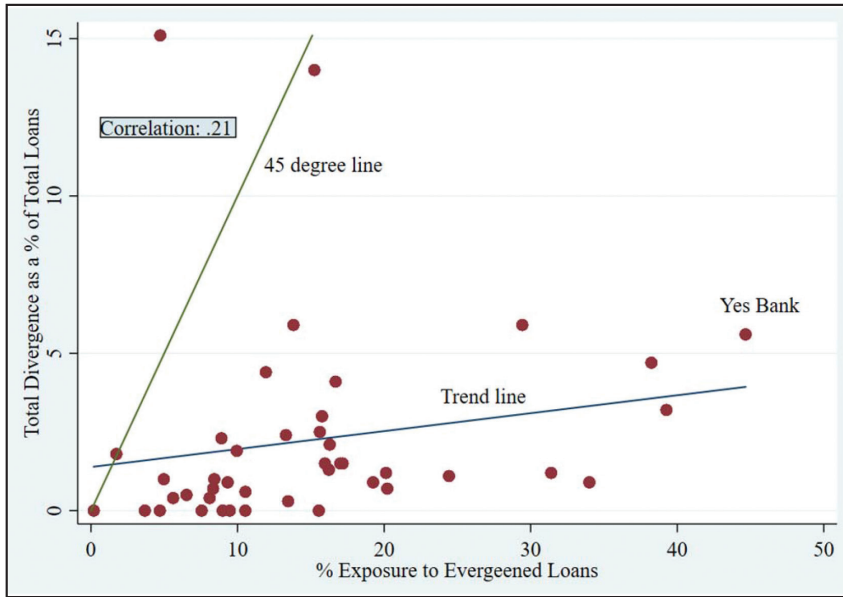
स्रोत: कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सीएमआईई कौशल।

चित्र: 23: एक्यूआर, अक्षय संभावना को नहीं पहचान पाया: जांबी प्रतिष्ठानों को ऋण के साथ विचलन का सहसंबंध न होना



स्रोत: कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सीएमआईई कौशल।

चित्र: 24: एक्यूआर, अक्षय संभावना को नहीं पहचान पाया: संबंधित पक्षों को ऋण के साथ विचलन का कमजोर सहसंबंध



स्रोत: कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सीएमआईई कौशल।

7.36 यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की हाल की घटनाओं ने पुष्टि की है कि एक्यूआर, औपचारिक पुनर्गठन के अतिरिक्त, अन्य माध्यमों से किए गए अक्षय कार्यकलापों पर नियंत्रण नहीं किया है। तालिका 6, यस बैंक लिमिटेड और लक्ष्मी विकास बैंक के सकल एनपीए अनुपात को प्रतिवेदित करती है। यदि एक्यूआर प्रयोग अक्षय कार्यकलापों का पता लग पाता, तो उनके प्रतिवेदित एनपीए में वृद्धि, एक्यूआर के प्रारंभिक वर्षों में पता चल जाती। हमारा विश्लेषण स्पष्टतः दर्शाता है कि अधिकांश गैर-निष्पादित ऋणों को छूट के चरण के दौरान दिया गया और पुनर्गठित किया गया। अतः आरबीआई लेखा परीक्षा में इन बैंकों द्वारा अक्षय कार्यकलापों के कुछ गंभीर मामलों को छोड़ दिया गया है। यह तथ्य कि इन दोनों बैंकों को नियामक द्वारा बचाया जाना

था, आरबीआई की धारणा के प्रतिकूल भी जाता है कि निजी बैंकों को क्लीन-अप उपरांत आवश्यक पूंजी जुटाने में सक्षम होना चाहिए।

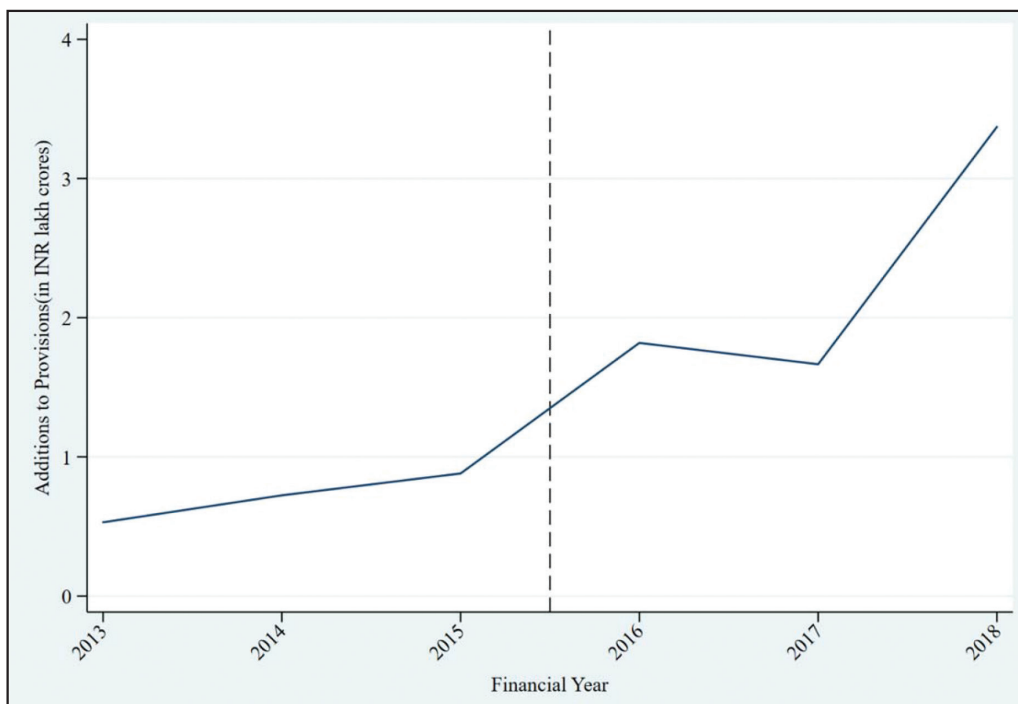
तालिका 6: यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक का सकल एनपीए

	यस बैंक लिमिटेड	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2016	0.76	1.97
वित्तीय वर्ष 2017	1.52	2.67
वित्तीय वर्ष 2018	1.28	9.98
वित्तीय वर्ष 2019	3.22	15.30
वित्तीय वर्ष 2020	16.80	25.39
दूसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2021 (लेखा परीक्षा रहित)	16.90	24.45

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट

7.37 यदि एक््यूआर द्वारा बैंक बुकों में छिपी सभी खराब गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियां को सही से पहचान लिया जाता, सभी एनपीए वृद्धि और आवश्यक प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2017 की कथित समयसीमा तक समाप्त किया जा सकता था। हालांकि भारतीय बैंक क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018 तक के केवल 11.2% की ही वृद्धि हुई है। ऋण-हानि प्रावधानों (लोन-लॉस प्रोविजनिंग) में भी वित्त वर्ष 2018 में भारी उछाल आया है-ए.क्यू.आर. के एक वर्ष पश्चात् बैंक बैलेंस शीट में काफी अच्छा होने की आशा थी जैसाकि चित्र 25 में दिखाया गया है। वित्त वर्ष 2018 के अतिरिक्त प्रावधान दोगुने हो गए। उदाहरणार्थ वित्त वर्ष 2016-17 में पंजाब नेशनल बैंक में क्रमशः 18,145 करोड़ रु. तथा 15,881 करोड़ रु. के अतिरिक्त प्रावधान किए गए। वित्त वर्ष 2018 में अतिरिक्त प्रावधान बढ़कर 31,459 करोड़ रु. हो गए। अतिरिक्त प्रावधानों से बैंकों की पूंजी में कमी आई।

चित्र: 25: एक््यूआर के अंतर्गत छिपी खराब परिसंपत्तियों की अपर्याप्त पहचान: एक््यूआर की पूर्णता के बाद एक वर्ष के प्रावधान करने में तीव्र वृद्धि



स्रोत: चोपड़ा, सुब्रमण्यन तथा तंत्री (2020)

अपेक्षित बैंक पूंजी का कम मूल्यांकन

7.38 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ए.क्यू.आर. के पूर्व जिस वास्तविक पूंजी का अनुमान लगाया था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपेक्षित वास्तविक पूंजी में इससे कहीं अधिक राशि हो गई है। ए.क्यू.आर. के प्रथम वर्ष में मिशन इंद्रधनुष के तहत आगामी तीन वर्षों के तहत 45,000/- करोड़ रुपए की इच्छित योजना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 25,000/- करोड़ रु. का निवेश किया गया हालांकि वित्त वर्ष 2019 के अंत तक अर्थात् ए.क्यू.आर. के सूत्रपात के चार वर्ष पश्चात् सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। वर्धित पूंजी का मूल्य कुल वर्धित सकल राशि का 44.24% बनता है। बॉक्स-8 में चोपड़ा, सुब्रमण्यन तथा तंत्री (2020) में से प्रतिगमन परिणामों को यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि सरकारी तथा निजी बैंकों में से दोनों ने संबद्ध व्ययपूर्ति के पश्चात् स्वयं का पर्याप्त रूप से पुनः पूंजीकरण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप बैंकों में काफी कम रह गई। यहां पर आर.बी.आई. का इस संदर्भ में यह मूल्यांकन याद करना होगा कि “जो सरकारी सहायता दर्शाई गई है वह पर्याप्त है..... तमाम उचित परिदृश्यों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त है।”

बॉक्स 8: बैंकों द्वारा अपर्याप्त पूंजी जुटाना

निम्नलिखित विनिर्देश का प्रयोग करते हुए चोपड़ा, सुब्रमण्यन तथा तंत्री (2020) ने लिखा है कि ए.क्यू.आर. के पश्चात् सरकारी तथा निधि बैंकों का कम पूंजीकरण हुआ।

$$Y_{it} = \beta_1 \times \text{एक्सपोजर}_{it} = \beta_2 \times \text{एक्सपोजर}_{it} \times \text{पी.एस.जी.}_i + \nu_i + \delta_t = \text{Cit}$$

यहां पर, बैंक वर्ष स्तर पर 2013-19 तक के वर्षों का डाटा रखा जाता है। दो आश्रित चर वस्तुएं हैं: (i) बैंक की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त पूंजी में कुल अनुवृद्धि, तथा (ii) बैंक की परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ए.क्यू.आर. के तहत प्रावधानों के विचलन को प्रदत्त पूंजी में से घटाकर कुल अनुवृद्धि। स्वतंत्र चर, ए.क्यू.आर. के लिए बैंक जोखिम हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक सूचक चर होता है। ए.क्यू.आर. हेतु बैंक जोखिम, ए.क्यू.आर. की वजह से प्रावधानों में बैंक द्वारा किए गए विचलन के बराबर होता है (कुल परिसंपत्तियों के % के रूप में) V_i और St का आशय क्रमशः बैंक तथा वर्ष के स्थिर प्रभावों से है। बैंक के तय प्रभाव यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बैंक विशिष्ट समय अपरिवर्तनीय प्रभाव, परिणामों को प्रभावित न करे। कॉलम (1) यह दर्शाता है कि ए.क्यू.आर.की वजह से रिपोर्टित अतिरिक्त प्रावधान जितने अधिक होंगे, उतना ही अधिक पूंजी निवेश होगा। कॉलम (2) दर्शाता है कि यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश की वजह से ही सत्य हुआ है। पूंजी निवेश की पर्याप्तता के बारे में, कॉलम (3) में ऋणात्मक और बहुत बड़ा गुणांक इंगित करता है कि पूंजी आधिक्य, ए.क्यू.आर की वजह से अतिरिक्त प्रावधानों को पूरा करने में व्यापक रूप से अपर्याप्त थे। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त प्रावधानों के लिए समायोजित किए जाने पर बैंक की पूंजी में वास्तव में कमी आती है।

	(1)	(2)	(3)
चर (वेरिएबल)	प्रदत्त पूंजी में वृद्धि (% में)		विचलन के लिए समायोजन के बैंक एक्सपोजर टू ए.क्यू.आर. (% में)
पब्लिक सैक्टर बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक)	0.1859** (2.2620)	-0.1247 (-1.2679)	-0.8141*** (-9.9030)

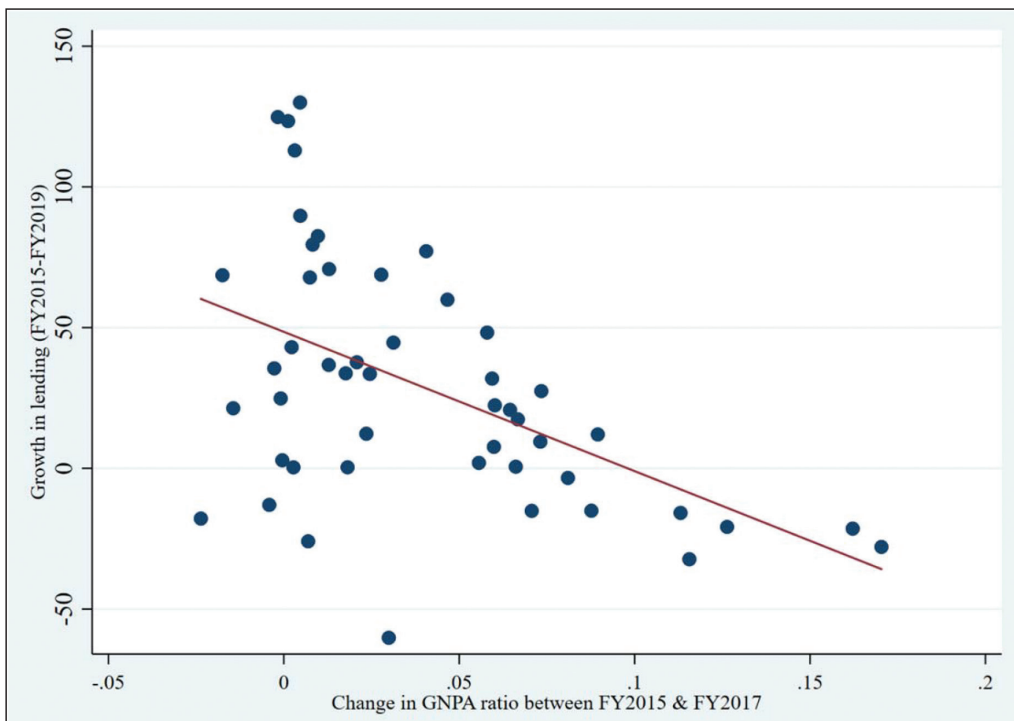
क्लस्टरिंग/गुच्छन		0.3902**	
		(2.6037)	
प्रेक्षण	297	297	297
आर. स्क्वैयर्ड	0.3023	0.3133	0.4251
एफ.ई	Bank & Year		
क्लस्टरिंग/गुच्छन	Bank		

तालिका: 7 यह तालिका उपर्युक्त समीकरण का उपयोग करते हुए पूंजी निवेश पर विचलन के प्रभाव के ओ.एल. एस. प्राक्कलन दर्शाती है। मानक त्रुटियों को बैंक के स्तर पर ही क्लस्टर किया जाता है तथा टी. आंकड़ें कोष्ठक में प्रतिवेदित हैं। पी. 0.1; <**पी. <0.05; ***, पी. <0.01 स्रोत: चौपड़ा, सुब्रह्मणियन तथा तंत्री (2020)

उधार पर प्रतिकूल प्रभाव:

7.39 चूंकि बैंक क्लिनअप के पश्चात् पर्याप्त मात्रा में नई पूंजी जुटाने में असमर्थ थे अतः उनके उधार में भी कमी आई। चित्र 26, प्रत्येक बैंक द्वारा उसके वर्ष 2017 के ग्रॉस एन.पी.ए. (ए.क्यू.आर. की शुरुआत के दो वर्ष पश्चात्) तथा 2015 (ए.क्यू.आर. के ठीक पूर्व) में अंतर के विरुद्ध उधार देने में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। ए.क्यू.आर. में से उत्पन्न एन.पी.ए. वृद्धि के पश्चात् उधार देने में काफी कमी आई थी। चित्र 27, जोकि बैंक की एन.पी.ए. में अंतर के विरुद्ध ज़ाम्बी फर्म्स (फर्जी फर्म) को उधार का शेयर दर्शाता है, यह सुझाता है कि प्रभावित बैंकों में जोखिम भरे उधारकर्ताओं के आने के मामलों में वृद्धि हुई। पूंजी में कमी और बढ़ते जोखिमपूर्ण उधार के बीच संबंधों पर आर्थिक तर्क पर बॉक्स-I में चर्चा की गई है। इस प्रकार पहले से ही तनावग्रस्त बैंकिंग क्षेत्र में ए.क्यू.आर. द्वारा जनित पूंजीकरण के तहत द्वितीय लहर से अनुत्पादक छद्म उधारकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि वितरण में अधिक वृद्धि हुई। बॉक्स-9 पैनेल रिग्रेशन का प्रयोग करते हुए इस साक्ष्य को दर्शाता है जो कि विभिन्न यौगिक कारकों को नियंत्रित करते हैं।

चित्र 26: बैंक उधार पर ए.क्यू.आर. का प्रभाव



स्रोत: सी.एम.आई.ई. प्रोवेस/कौशल एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

समग्र ऋण में कमी:

चौपड़ा, सुब्रमणियम तथा तंत्री (2020) ने बैंकिंग क्षेत्र द्वारा समग्र ऋण पर ए.क्यू.आर. के प्रभाव लिखने में निम्नलिखित पैनेल रिग्रेशन का प्रयोग किया:-

$$(ऋण राशि X+B, X \text{ एक्सपोज़र } \tau \text{ ए.क्यू.आर. } +B_2+X_{it}+it+S,+E_{it}$$

यहां पर प्रमुख निर्भर चर (आई.) बैंक द्वारा वित्त वर्ष (टी.) के दौरान फर्म को दी गई कुल राशि का प्राकृतिक (जे.) लघुगणक (लोगारिद्म) है। अवलोकन, फर्म ऋणदाता वर्ष स्तर पर है। एक्सपोज़र को ए.क्यू.आर. की बजह से ऋणदाताओं द्वारा प्रावधानों में विद्यमान के तौर पर परिभाषित किया गया है। (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)। जो किसी भी समय भिन्न फर्म स्तरीय प्रवृत्ति नियंत्रित करता है अर्थात ऋण के लिए फर्म-स्तरीय मांग में किसी भी तरह के विचलन/परिवर्तन को नियंत्रित करती है। S, समय अपरिवर्तनीय ऋणदाता स्तर के प्रभावों को केचर करता है। समय के साथ परिवर्तनीय फर्म-लैंडर वार्षिक स्तर के रूझानों को नियंत्रित करने वाले चर हैं। परिणाम निम्नलिखित हैं।

	(1)	(2)	(3)	(4)
VARIABLES	लॉग (ऋण की राशि)			
Exposure to AQR (%)	-0.3484***	-0.2826*	-0.2156**	-0.2899*
	(-3.6049)	(-1.7049)	(-2.3061)	(-1.7165)
Observations	167,674	167,674	167,674	167,674
R-squared	0.3044	0.3393	0.3118	0.3453
Controls	No	No	Yes	Yes
FE	Firm X Year	Firm X Year & Lender	Firm X Year	Firm X Year & Lender
Clustering	Firm	Lender	Firm	Lender

तालिका 8: यह तालिका उपर्युक्त समीकरण के ओ.एल.एस. प्राक्कलन की रिपोर्ट देती है। मानक त्रुटियों को समसंख्यक स्तंभों में फर्म-स्तर पर ही क्लस्टर किया जाता है तथा लैंडर लेवल को विषम संख्या वाले में। टी(t) आंकड़ों को कोष्ठक में दर्शाया गया है। *पी <0.1, **पी < .05, ***<0.01 स्रोत:- चौपड़ा, सुब्रमणियम तथा तंत्री (2020)

गुणांक ऋणात्मक होते हैं तथा सांख्यिकीय लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यह इंगित करता है कि जितना अधिक बैंक का एक्सपोज़र होता है, ए.क्यू.आर.के पश्चात् उतना ही अधिक उसकी ऋण आपूर्ति में कमी आती है। आर्थिक परिणाम के संदर्भ में ए.क्यू.आर. के कारण एक्सपोज़र में एक मानक विचलन बढ़ने से बैंक ऋण में 4% तक की कमी आती है।

समग्र ऋण और समग्र जोंबी (छद्म) उधार पर कम पूंजी का प्रभाव: चौपड़ा , सुब्रमणियम तथा तंत्री (2020) निम्नलिखित प्रतिगमन विनिर्देशन, ऋण पर पूंजीकरण का प्रभाव दिखाता है।

$$\begin{aligned} \text{Log}(\text{Loan Amount}_{ijt}) = & \alpha + \beta_1 \times \text{Exposure to AQR}_{it} + \beta_2 \times \text{Zombie}_{(j,t-1)} + \beta_3 \times \text{Capital} \\ & \text{AdequacyRatio}_{it} + \beta_4 \times \text{Exposure to AQR}_{it} \times \text{Zombie}_{(j,t-1)} + \beta_5 \times \text{Exposure to AQR}_{it} \times \text{CAR}_{it} + \beta_6 \\ & \times \text{Zombie}_{(j,t-1)} \times \text{CAR}_{it} + \beta_7 \times \text{Exposure to AQR}_{it} \times \text{Zombie}_{(j,t-1)} \times \text{Capital AdequacyRatio}_{it} + \beta_8 \\ & \times X_{ijt} + v_{jt} + \delta_i + \text{epsilon}_{ijt} \end{aligned}$$

ये प्रेक्षण एक फर्म-लैंडर वर्ष स्तर पर है। आश्रित चर, (आई.) ऋणदाता द्वारा एक वर्ष (टी) में एक फर्म (i) को दिए गए कुल ऋण राशि का प्राकृतिक लघुगणक है। महत्वपूर्ण स्वतंत्र चर है:-

- (i) ए.क्यू.आर. की वजह से ऋणदाता द्वारा प्रावधानों में विचलन के तौर पर एक्सपोज़र (निवेश) (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)
- (ii) सी.ए.आर. को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, तथा
- (iii) जॉम्बी को एक ऐसे सूचक चर के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि ब्याज कवरेज अनुपात संबंधित पार्टी लेने-देने से किसी भी आय के लिए समायोजित के एक या शून्य से कम होने पर एक के बराबर होता है अन्यथा टी-1 वर्ष में रहता है तथा क्रमशः किसी भी समय के अलग-अलग स्तर की प्रवृत्ति तथा समय अपरिवर्तनीय ऋणदाता के स्तर प्रभावों को नियंत्रित करता है। समय के साथ परिवर्तनीय फर्म ऋणदाता वर्ष स्तर के रूझानों/प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाले चर हैं।

	(1)	(2)	(3)	(4)
चर	लॉग (लॉग राशि)			
ए.क्यू.आर. एक्सपोज़र(%)	-0.6264***	-0.6476***	-4.8615***	-4.8462***
	(-2.6718)	(-2.7588)	(-4.3438)	(-4.5303)
पूंजी पर्याप्तता अनुपात			0.0076	0.0070
			(1.5617)	(1.5173)
ए.क्यू.आर. एक्सपोज़र(%) X			0.3763***	0.3724***
			(3.8534)	(3.9497)
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	0.7216***	0.7509***	3.9556***	3.9325***
	(3.3870)	(3.6242)	(3.3956)	(3.5502)
ए.क्यू.आर. एक्सपोज़र(%) X जॉम्बी			-0.0039	-0.0036
			(-0.7303)	(-0.6736)
पूंजी पर्याप्तता अनुपात X जॉम्बी			-0.2752***	-0.2682***
			(-3.0560)	(-3.0201)
प्रेक्षण	117,827	117,827	83,977	83,977
आर. स्क्वेयर्ड	0.3202	0.3265	0.3506	0.3567
नियंत्रण	नहीं	हां	नहीं	हां
एफ.ई.	फर्म X वर्ष एवं ऋणदाता			
क्लस्टरिंग	ऋणदाता			

तालिका 9: यह तालिका ऋण पर ए.क्यू.आर. के प्रभाव का ओ.एल.एस. प्राक्कलन करती है। मानक त्रुटियों को ऋणदाता के स्तर पर ही गुच्छित कर लिया जाता है तथा वही आंकड़े कोष्ठक में सूचित किए जाते हैं। *पी < 0%, **पी < 0.5%, ***पी < 0.01% स्रोत: चौपड़ा सुब्रहमणियन तथा तंत्री (2020)।

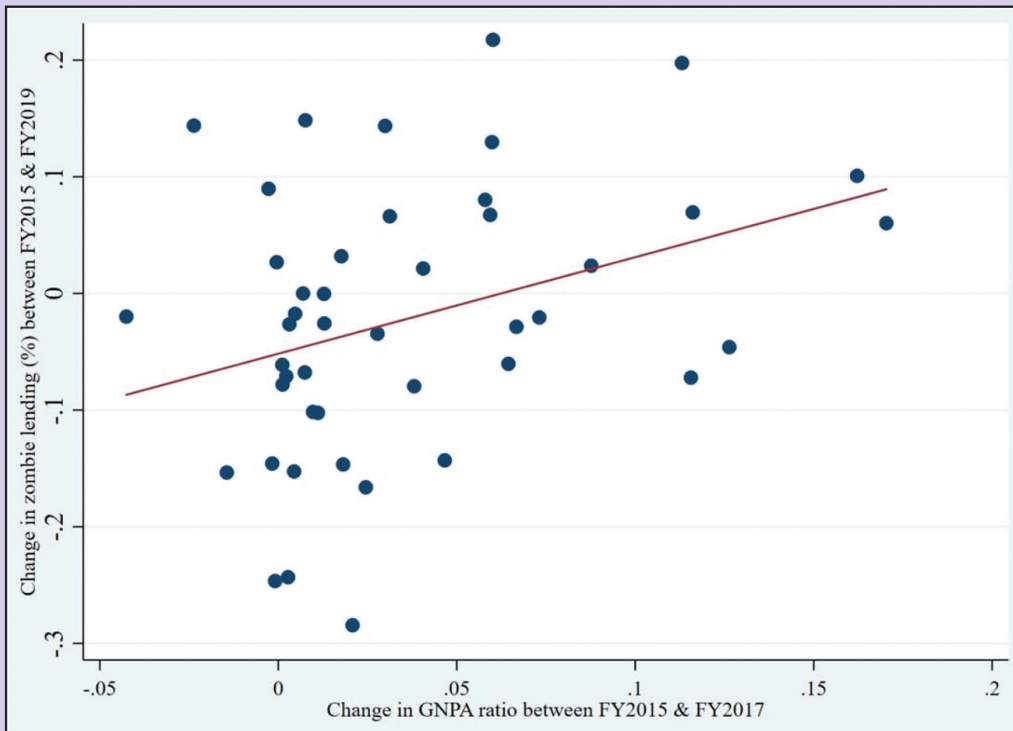
तालिका-9 में सभी स्तंभों में हम देखते हैं कि ए.क्यू.आर. की वजह से ऋण में कमी आई है जैसा कि ए.क्यू.आर. से चर एक्सपोजर का निरंतर ऋणात्मक गुणांक देखा गया है। पहले दो कॉलमों में इन्टरैक्शन टर्म के लिए घनात्मक गुणांक यह दर्शाता है कि हालांकि समग्र ऋण देने में कमी आई है परंतु फिर भी छद्म (Zombie) फर्मों को ए.क्यू.आर. के पश्चात् अधिक ऋण बांटा गया है। इस प्रकार ए.क्यू.आर. के बाद भी जॉम्बी फर्मों ऋण संकुचन से कम प्रभावित थीं।

कॉलम (3) व (4) में एक्सपोजर तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात के मध्य इन्टरैक्शन का घनात्मक गुणांक अनुमान यह इंगित करता है कि कम पूंजी के ऋण पर ए.क्यू.आर. के प्रभाव को बढ़ा दिया। यह देखने के लिए ए.क्यू.आर. पर जोखिम एक्सपोजर के उपांतिक प्रभाव को नोट किया जाना चाहिए जो आंशिक अवकलन, (ऋण)/(ए.क्यू.आर. एक्सपोजर) द्वारा दिया गया है तथा $-4.8 + 3.9* \text{जॉम्बी} + 3.8 \text{ पूंजी पर्याप्तता अनुपात} - 0.27* (\text{जॉम्बी} * \text{पूंजी पर्याप्तता अनुपात})$ के बराबर है। चूंकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात का गुणांक चिह्न घनात्मक (+) है, यह इंगित करता है कि ऋण पर ए.क्यू.आर. का आंशिक प्रभाव, कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ बैंकों के लिए अनुपातहीन रूप से अधिक है। इसके अतिरिक्त इन्टरैक्शन टर्म जॉम्बी* पूंजी पर्याप्तता अनुपात का चिह्न, इस उपांतिक प्रभाव में ऋणात्मक है, जो इंगित करता है कि कम पूंजी वाले बैंकों के साथ संबद्ध जॉम्बी फर्मों के ऋण में कम गिरावट दर्ज की गई।

फर्म के पूंजीगत निवेश में गिरावट

7.40 बैंक द्वारा ऋण आपूर्ति सीमित किए जाने से यथेष्ट उधारकर्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि इससे फर्मों को उनके निवेश तथा पूंजी व्यय में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार पहले से चल रही परियोजनाओं के रुकने की संभावना में वृद्धि हुई। चित्र-28 फर्मों की रुकी हुई परियोजनाओं के मूल्य को दर्शाता है। जब गैर-प्रभावित बैंकों के साथ संलग्न फर्मों के साथ ए.क्यू.आर. द्वारा प्रभावित बैंकों पर अनाश्रित फर्मों की तुलना की गई तो यह ज्ञात हुआ कि फर्मों के लिए ए.क्यू.आर. के बाद रुकी हुई परियोजनाओं के मूल्य में काफी वृद्धि हुई।

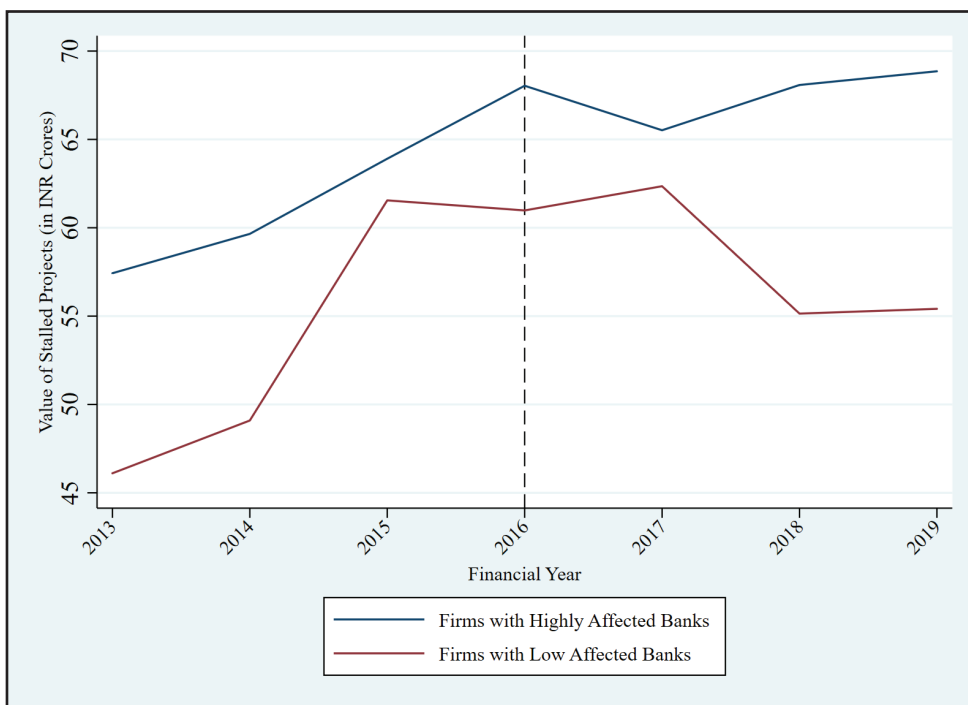
चित्र 27: जॉम्बी लैंडिंग पर ए.क्यू.आर. का प्रभाव



स्रोत: सी.एम.आई.ई. प्रोवैस।

टिप्पणी/नोट: जॉम्बी लैंडिंग द्वारा एक से कम ब्याज कवरेज वाली फर्मों को ऋण देने के अनुपात को मापा जाता है।

चित्र 28: फर्मों का पूंजी निवेश-रुकी परियोजनाओं की कीमत



स्रोत: सी.एम.आई.ई. प्रोवैस

7.41 कुल मिलाकर, ए.क्यू.आर. के तहत शुरू किया गया बैंक बैलेंस शीट्स का परिशोधन कार्य से फॉरबीयरेंस की-दीर्घ अवधि द्वारा जनित समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं। ऋण देने के मामले में, कम पूंजीकरण की वजह से बैंकों ने अच्छे उधारकर्ताओं को ऋण देना कम कर दिया है तथा छद्म (जॉम्बी) उधारकर्ताओं को अधिक ऋण देना शुरू किया है। फर्मों के लिए बैंक ऋण में कटौती की वजह से उनके निवेश करने की क्षमता भी कम हो गई है। चौपड़ा, सुब्रमणियन तथा तंत्री (2020) ने ए.क्यू.आर. की तुलना अन्य क्लीन-अप कार्यक्रमों से की तथा इस प्रकार के क्लीन अप के पूर्व एक स्पष्ट पुनर्पूँजीकरण कार्यक्रम, बलात् अन्यथा, की आवश्यकता की ओर इंगित किया।

वर्तमान फॉरबीयरेंस व्यवस्था के निहितार्थ:

विनियामक फॉरबीयरेंस के गहन, सावधानीपूर्वक विश्लेषण तथा परिणामी बैंकिंग संकट से कोविड संकट के पश्चात् विनियामक फॉरबीयरेंस की वर्तमान व्यवस्था से महत्वपूर्ण सीख मिली है। अंततः

- (क) याद रखें कि (फॉरबीयरेंस) आपातकालीन समाधान है जिसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के सही-हालत में वापिस आ जाने पर रोक दिया जाना चाहिए, ऐसा न हो कि इसका इस्तेमाल कई-वर्षों तक एक प्रमुख उपाय के रूप में किया जाता रहे। इसलिए नीति निर्माताओं को ऐसी अर्थव्यवस्था रिकवरी की सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए जहां पर पहुंचकर ऐसे उपाय वापस लिए जाने चाहिए। बैंकों को इस प्रकार की सीमाओं की पूर्व जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे इसकी तैयारी पहले से ही कर पाएं। सर्वेक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि उक्त फॉरबीयरेंस को जारी रखने के लिए पैरवी करने या दबाव बनाने के बावजूद कुछ तिमाहियों के लिए मजबूत आर्थिक सुधार, वापस लिए जाने का कारण बन सकता है। दीर्घकालिक फॉरबीयरेंस दिए जाने से यह संकट और अधिक गहरा सकता है। साथ-साथ फॉरबीयरेंस दिए जाने पर एक स्वस्थ उधार संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए जांबी (Nne) ऋण पर प्रतिबंध

भी लगाया जाना चाहिए। ये प्रतिबंध एक सीमा तक लाभांश पर लगाए जा सकते हैं तथा ऐसे ऋण के प्रकार पर भी संबंधित पक्ष (पार्टी) लेन-देन पर भी लगाए जा सकते हैं जो फॉरबीयर्स व्यवस्था के तहत दिए गए हों।

- (ख) फॉरबीयर्स समाप्त किए जाने पर बैंक बैलेस शीट के (क्लीन-अप) शोधन भी आवश्यक है। ध्यान दें कि जब 2016 ए.क्यू.आर. ने बैंकिंग क्षेत्र में समस्याओं को बढ़ा दिया था, तब वहां से यह सबक नहीं मिला कि ए.क्यू.आर. न किया जाए। विनियामक तथा बैंकों के बीच असीमित जानकारी की समस्या को देखते हुए, जो कि फॉरबीयर्स व्यवस्था के दौरान और अधिक बढ़ जाती है, फॉरबीयर्स समाप्त करते समय तुरंत ए.क्यू.आर. की जानी चाहिए।
- (ग) परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा में ऐसे सभी रचनात्मक तरीकों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिनके द्वारा बैंक अपने ऋणों को एवरग्रीन बनाए रख सके। इस संदर्भ में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जो अग्रिम चेतावनी संकेतक सही सरोकारों को चिन्हित करने का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते वे सुरक्षा का छद्म भाव उत्पन्न कर सकते हैं। बैंकिंग विनियामकों को त्रुटि लाईनों की शीघ्र पहचान के लिए और अधिक तैयार किया जाना चाहिए तथा प्रत्याशित उपचारात्मक उपायों की टूलकिट का विस्तार भी होना चाहिए।
- (घ) अनिवार्य पूंजी निवेश के साथ क्लीन-अप से अप्रत्याशित ऋण शोधन प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। बैंकों से यह अपेक्षा किया जाना कि आर्थिक सुधार की वजह से वे अपना पुनर्पूँजीकरण स्वयं करें, विवेकपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए शोधन प्रक्रिया के साथ अनिवार्य पुनर्पूँजीकरण भी किया जाना चाहिए जो एक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के पश्चात् पूंजी आवश्यकताओं के गहन मूल्यांकन पर आधारित हो।
- ड. बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के अलावा उनके शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करना भी महत्वपूर्ण है। बैंकों द्वारा ऋण की एवरग्रीनिंग के साथ-साथ जॉम्बों-लैँडिंग कुशासन ही दर्शाता है तथा यह सुझाता है कि बैंक बोर्ड “प्रसुप्त” अवस्था में है तथा लेखापरीक्षक प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इसलिए रियायतों का वर्तमान चरण समाप्त होने के पश्चात् जॉम्बों-लैँडिंग तथा एवरग्रीनिंग से बचने के लिए एक ओर तो बैंकों का पूरी तरह से सशक्त ऐसा सक्षम बोर्ड होना चाहिए जिन्हें शासन व्यवस्था तथा उसका प्रबंधन कार्य सौंपा जा सके। सुशासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख मीट्रिक है (परिमाणात्मक) है कि बैंक, पूंजी निवेश के उपरांत विरूपणकारी लैँडिंग में संलिप्त न हों। अपितु यदि पूर्वोपायों की टूलकिट के भाग के रूप में एवरग्रीनिंग पाई जाती है तो विनियामक में बैंक ऑडिटर्स पर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। इससे लेखापरीक्षकों को वित्तीय पर्यवेक्षण कर्मठतापूर्वक करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
- च. हालांकि पिछले प्रकरण से मिली सीख का इस्तेमाल पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाना चाहिए तथापि, सर्वेक्षण समीक्षा के अध्याय-7 में वर्णित परिज्ञान द्वारा शासित जटिल घटनाओं का कार्योंत्तर विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। विशेष रूप से इस अस्थिरता के बीच निर्णय शासित करने वाली नीति/निर्धारण के लिए पूर्वव्यापी कार्य की जांच में पश्चदृष्टि पूर्वाग्रह की भूमिका को भी स्वीकार करना चाहिए तथा खराब परिणामों की वजह से गलत निर्णय या कदाशय उद्देश्य के साथ प्रतिकूल परिणामों वाली गलती नहीं करनी चाहिए।
- छ. अंत में ऋण वसूली के लिए विधिक अवसंरचना को भी वस्तुतः मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। दिवालिया तथा दिवालियापन कोड (आई.बी.सी.) में ऋणदाताओं को चूककर्ताओं पर शास्ति अधिरोपित

करने की कानूनी शक्तियां दी गई हैं। हालांकि आई.बी.सी. के कार्यान्वयन के लिए विधिक अवसंरचना में ऋण वसूली न्यायाधिकरण; राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण तथा अपीलीय न्यायाधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए कि ऋणदाता के रूप में बैंकों को, चूककर्ता उधारकर्ताओं को दंडित करने में वास्तव में अधिक शक्तियां प्राप्त हों।

अध्याय एक नजर में

- वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, प्रविरिति ने उधारकर्ताओं को इस संकट के कारण उत्पन्न अस्थायी कठिनाई को हराने और इस महामारी की रोकथाम में सहायता की है।
- हालांकि, आर्थिक बहाली के कफी बाद तक प्रविरिति जारी रही, परिणामस्वरूप बैंक, प्रतिष्ठानों और अर्थव्यवस्था के लिए अनप्रेक्षित और क्षतिकारक परिणाम प्राप्त हुए।
- दी गई शिथिल प्रावधान आवश्यकताओं, का बैंकों द्वारा अलाभकारी संस्थाओं तक के लिए पुनर्गठित ऋणों के लिए प्रविरिति विंडों का दोहन किया, जिससे बैंकों ने अपनी बुकों की विंडोड्रेसिंग की।
- विकृत प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप बैंकों ने जमा धन को गलत आवंटित किया, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा।
- प्रविरिति, आपातकालीन औषधि के रूप में है जिसे अर्थव्यवस्था द्वारा बहाली प्रदर्शन के प्रथम अवसर पर देन बंद देना चाहिए। इसे मुख्य भोजन की तरह वर्षों तक जारी नहीं रखना चाहिए।
- अनिश्चितता के बीच सही निर्णय पर पहुंचने के लिए नीति-निर्माण हेतु कार्योत्तर जांच में दूरदर्शितापूर्ण, पूर्ण पक्षपात के महत्व को समझना चाहिए तथा अप्रत्याशित नतीजे या गलत निर्णय को दुर्भावना जैसे अनुचित परिणामों से बचना चाहिए।
- नियामकों और बैंकों के मध्य विषम सूचना की समस्या को देखते हुए जो प्रविरिति व्यवस्था के दौरान स्पष्ट हुई, प्रविरिति वापसी के तुरंत बाद संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा उपाय किया जाना चाहिए।
- वास्तव में ऋण वापसी के लिए विधि-सम्मत आधारिक संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता है।

REFERENCES:

- Admati, A., & Hellwig, M. (2014). *The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do about It-Updated Edition*. Princeton University Press.
- Chari, A., L. Jain, and N. Kulkarni (2019): "The Unintended Consequences of Regulatory Forbearance," *Working Paper*.
- Chopra, Y., Nishesh, N., and Tantri, P. 2020. "Does Regulatory Forbearance On Bank Loans Adversely Impact Governance of Borrowing Firms?: The Indian Experience.," *Working Paper*
- Chopra, Y., Subramanian, K., and Tantri, P. 2020. "Bank Cleanups, Capitalization, and Lending: Evidence from India." *The Review of Financial Studies*.
- Diamond, D.W. and Dybvig, P.H., 1983 "Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity", *Journal of Political Economy*, Volume 91 Number 3
- Diamond, D. W. and R. G. Rajan (2011): "Fear of fire sales, illiquidity seeking, and credit freezes," *The Quarterly Journal of Economics*, 126, 557-591
- Jensen, M.C. and Meckling, W.F., 1976, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure", *Journal of Financial Economics*, Volume 3, Issue 4, 305-360
- Kashyap, N., Mahapatro, S., and Tantri, P., 2020, "They will do it anyway: Unearthing indi-

rect evergreening”, *Working Paper* Myers, S. C. (1977): “Determinants of corporate borrowing,” *Journal of financial economics*, 5, 147-175

Mannil, N., Nishesh, N., & Tantri, P. (2020). Medicine Or An Addictive Drug?: The Vicious Cycle Of Regulatory Forbearance. *Working Paper*

Modigliani, F. and Miller, Merton H. 1958, The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, *American Economic Review*, Volume 48, No. 3 (261-297)

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have (No. w1396). National Bureau of Economic Research. P.J.Nayak Committee Report - Report of the Committee to Review Governance of Boards of Bank, Page 27. Reserve Bank of India, May 2014

Rajan, R. 2016. Issues in banking today, Page 1. Reserve Bank of India Rajan, R. 2014, Address at the Tenth Convocation of PGPBF (Batch 2012-14) at NIBM, Pune on April 04, 2014

Sarkar, A., Subramanian, K., & Tantri, P. (2019). Effects of CEO Turnover in Banks: Evidence Using Exogenous Turnovers in Indian Banks. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 54(1), 183-214. Tantri, P. 2020, “Identifying Zombie Lending: Evidence Using Loan-Level Data”, *Journal of Banking and Finance (Forthcoming)*.